

तरुण छत्तीसगढ़

आम आदमी का अपना दैनिक अखबार

E-mail:
tarunpressraipur@gmail.com
tarun_press@yahoo.co.in

Web:
www.tarunchhattisgarh.in
facebook.TarunChhattisgarh
phone: 0771-2543112

■ रायपुर,शनिवार 28 नवंबर 2026 ■ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष-3 ■ वर्ष -42 ■ अंक-238 ■ पृष्ठ 8 ■ डाक संस्करण 29 नवंबर 2026 ■ मूल्य-2.00 रुपये

अफगानिस्तान के स्कूल में धमाका, कम से कम 6 स्टूडेंट्स की मौत

कंधार,28 नवंबर। अफगानिस्तान के उत्तर-पूर्वी प्रांत कुनार के शनिवार को एक स्कूल में धमाका हुआ है। इस ब्लास्ट में कम से कम 6 स्टूडेंट्स की मौत हो गई, जबकि 97 घायल हैं। कुनार प्रोविंशियल अस्पताल के प्रमुख मावला दाद ने 'अल जजीरा' को धमाके के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ये आंकड़े शुरुआती हैं और ज्यादा जानकारी मिलने पर मरने वालों की संख्या बढ़ भी सकती है। कुनार में इन्फॉर्मेशन और कल्चर के डायरेक्टर मावलावी समी-उल-हक ने जानकारी दी कि यह धमाका पूर्वी अफगानिस्तान के कुनार प्रांत के अंदार सेर इलाके में एक मिडिल स्कूल के पास एक घर में शनिवार सुबह करीब 10 बजे हुआ है। यह घर माइनिंग के काम में शामिल लोगों का था, जिन्होंने वहां डायनामाइट जमा कर रखा था। धमाके के तुरंत बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। पाकिस्तान के बॉर्डर पर मौजूद कुनार प्रांत की जांच टीमें ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर पहुंचीं और यह जानने की कोशिश में जुट गई हैं कि आखिर ब्लास्ट कैसे हुआ। इससे पहले, अगस्त में काबुल के एक स्कूल में हैंड ग्रेनेड से ब्लास्ट हुआ था। उसमें 40 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी। सभी की उम्र महज 9 से 40 साल के बीच थी। इस धमाके के बाद प्राइवेट प्राइमरी स्कूल ने अपने फेसबुक पेज पर एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें लोगों से मृतकों और घायलों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा गया। तालिबान सरकार के पिछले पांच सालों के राज में काबुल में कई हमले हुए हैं। इसमें जनवरी में एक सेंट्रल चाइनीज रेस्टोरेंट में हुआ धमाका भी शामिल है। इसमें कम-से-कम सात लोग मारे गए थे। दश्त-ए-बारची इलाके में कई जानलेवा धमाके हुए हैं, जिसमें 2021 में एक गर्ल्स स्कूल के बाहर हुआ कार बम धमाका भी शामिल है। इसमें 90 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। इस्लामिक स्टेट ग्रुप ने दश्त-ए-बारची में हुए हमलों की जिम्मेदारी ली थी।

महिला आरक्षण पर पीएम मोदी ने कहा-हमारा हौसला भी बुलंद है, हिम्मत भी अटूट है

नई दिल्ली,28 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 'नारी शक्ति' को आरक्षण देने के अपने वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब केंद्र सरकार संसद के तीन दिवसीय विशेष सत्र के दौरान महिला आरक्षण से जुड़े परिसीमन विधेयक (डिलिमिटेशन बिल) को फिर से पेश करने की योजना बना रही है। संसद का यह विशेष सत्र सोमवार, 30 नवंबर से शुरू होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने X पर एक वीडियो संदेश पोस्ट करते हुए कहा कि हमने अपनी नारी शक्ति से एक वादा किया था और हम उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वीडियो में लिखा है, "हमारा हौसला भी बुलंद है। हमारी हिम्मत भी अटूट है।" केंद्र ने संसद का तीन दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है। केंद्र सरकार को भरोसा है कि प्रस्तावित परिसीमन विधेयक के मसौदे में जरूरी बदलाव करने के बाद, इसे संसद में पारित कराने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत मिल जाएगा। सरकार संसद की आगामी कार्यवाही से पहले विधायी एजेंडे पर चर्चा करने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों से संपर्क कर रही है। माना जा रहा है कि इन महत्वपूर्ण विधेयकों पर व्यापक विचार-विमर्श होगा और इन पर मतदान भी कराया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, सोमवार (30 नवंबर) सुबह 10 बजे 'बिजनेस एडवाइजरी कमिटी' की बैठक होगी, जिसमें संसद में पेश किए जाने वाले विधायी कार्यों को लेकर सभी दलों के प्रतिनिधियों से सलाह-मशविरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 1 दिसंबर को लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया पूरी होने में लगभग पांच से छह घंटे का समय लग सकता है। यह प्रस्तावित विधेयक केंद्र सरकार की उस योजना से जुड़ा है, जिसके तहत संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया जाना है, विधायिकाओं में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी है और निर्वाचित निकायों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना है।



परिसीमन से होगा छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास: साय

■ तरुण छत्तीसगढ़

रायपुर,28 नवंबर। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक और महिला आरक्षण को लेकर प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। इसको लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र बढ़ेगा, छत्तीसगढ़ का विकास होगा। साथ ही ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें परिसीमन से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक और महिला आरक्षण को लेकर प्रस्तावित बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में 50 फीसदी तक वृद्धि का प्रावधान है। साथ ही महिलाओं के लिए 33 फीसदी आरक्षण को 2029 के लोकसभा चुनाव से लागू करने का रास्ता तैयार करने की कोशिश की गई है। इसके लागू होने पर छत्तीसगढ़ में विधानसभा की मौजूदा 90 सीटें बढ़कर 135 और लोकसभा की 11 सीटें बढ़कर 17 हो सकती हैं। यानी छत्तीसगढ़ को 45 नए विधायक और 6 अतिरिक्त सांसद मिल सकते हैं। धान खरीदी को लेकर उन्होंने कहा कि खरीदी की लगातार समीक्षा की जा रही है। धान खरीदी को लेकर किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि धान खरीदी अच्छे से चल रही है और इसकी लगातार पूरी समीक्षा की जा रही है। लक्ष्मी वर्मा के सड़क हादसे को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि वह ठीक हैं। सड़क दुर्घटना में उन्हें थोड़ी चोट आई है, लेकिन उनकी स्थिति ठीक है।



छत्तीसगढ़ी भाषा हमारी संस्कृति, अस्मिता और स्वाभिमान की पहचान : मुख्यमंत्री

रायपुर 28 नवंबर. मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारी माटी की सोंधी महक, पुरखों के संस्कार और छत्तीसगढ़ की आत्मीयता रची-बसी है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ी भाषा हमारी सांस्कृतिक विरासत और स्वाभिमान का प्रतीक है। हमारे लोकगीतों, लोककथाओं, तीज-त्योहारों और परंपराओं में छत्तीसगढ़ी की मिठास और आत्मीयता झलकती है।

दिल्ली-एनसीआर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम

नई दिल्ली,28 नवंबर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-NCR) में सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है। एक गुप्त ऑपरेशन के दौरान पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन 'जैश-ए-मोहम्मद' (JeM) से जुड़े एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। सोशल मीडिया पर 'उमर' नाम से सक्रिय इस आरोपी पर आरोप है कि वह डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं का ब्रेनवॉश कर उन्हें कट्टरपंथी बना रहा था और देश में आतंकी हमलों को अंजाम देने के लिए उकसा रहा था। गिरफ्तारी के बाद संदिग्ध को आगे की गहन पूछताछ और कानूनी कार्रवाई के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया गया है। शुरुआती जांच में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 'इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस' (ISI) समर्थित आतंकी नेटवर्क से इसके सीधे तार जुड़े होने के संकेत मिले हैं। अधिकारियों ने बताया कि सोशल मीडिया पर 'उमर' नाम से सक्रिय इस आरोपी को बाद में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंप दिया गया। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए कई युवाओं के संपर्क में था। आरोप है कि उसने इन युवाओं को कट्टरपंथी बनाया और उन्हें आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए प्रेरित किया। जांच में एक ऐसे डिजिटल नेटवर्क का पता चला है, जिसका संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी 'इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस' (ISI) समर्थित आतंकी समूह से बताया जा रहा है। आरोपी से जुड़े कई लोगों से पूछताछ की गई है, हालांकि अभी तक कोई और गिरफ्तारी नहीं हुई है।

स्टालिन ने किया परिसीमन बिल के समर्थन का ऐलान

नई दिल्ली,28 नवंबर। केंद्र सरकार संसद के विशेष सत्र के दौरान परिसीमन बिल पेश करने जा रही है। इसकी तैयारी भी लगभग संपन्न हो चुकी है। इस संविधान संशोधन विधेयक के लिए जरूरी दो तिहाई बहुमत का जुगाड़ हो चुका है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार ने तमिलनाडु की डीएमके से मिली सहमति के बाद ही परिसीमन से जुड़े संशोधनों को पेश करने के लिए 30 नवंबर से संसद का एक विशेष सत्र बुलाया गया है। डीएमके चीफ एमके स्टालिन ने भी परिसीमन विधेयक के समर्थन का ऐलान कर दिया है। स्टालिन ने कहा कि अप्रैल वाले बिल में डीएमके ने जो दो शर्तें रखी थीं, दोनों मान ली गई हैं। यह पार्टी की बड़ी जीत है। स्टालिन ने समर्थन का ऐलान करते हुए लिखा, "डीएमके उस विधेयक का समर्थन करती है जिसमें निष्पक्ष परिसीमन की मांगों को शामिल किया गया है। जिन दो मांगों को लेकर हमने पिछले अप्रैल में परिसीमन विधेयक का विरोध किया था, उन्हें नए विधेयक में लिखित रूप से शामिल कर लिया गया है। यह 2024 से डीएमके द्वारा किए जा रहे निरंतर संघर्षों की जीत है। यह तमिलनाडु सहित सभी दक्षिणी राज्यों की जीत है।" उन्होंने आगे कहा, "हमें बिना भावुक हुए शांति से इस बात पर विचार करना चाहिए कि अगर हम इस परिसीमन विधेयक को हाथ से जाने देते हैं तो क्या होगा? इस विधेयक में 1971 की जनसंख्या के आधार पर सभी राज्यों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों में 50% की वृद्धि का प्रावधान है। इन सभी मुद्दों की अच्छी तरह से जांच करने के बाद डीएमके ने आज सांसदों की बैठक में परिसीमन के इस स्वरूप का समर्थन करने का निर्णय लिया है, जो व्यावहारिक रूप से संभव है और हमारे लिए फायदेमंद है।"' आपको बता दें कि पहले 27 नवंबर की सुबह डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें संसदीय दल की नेता कनिमोझी और पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा की। इससे पहले स्टालिन ने केंद्र सरकार को याद दिलाया था कि डीएमके ने हमेशा निष्पक्ष परिसीमन की वकालत की है। उन्होंने सरकार के सामने दो मांगें रखी थी। पहला यह था कि अगर लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाई जाती है, तो लोकसभा में तमिलनाडु की मौजूदा 7.18 प्रतिशत सीटों की हिस्सेदारी किसी भी हाल में कम नहीं होनी चाहिए। उनका यह भी कहना था कि 1971 की जनगणना के आधार पर तय किया गया राज्यों के बीच सांसदों की संख्या का मौजूदा अनुपात अगले 25 वर्षों तक वैसा ही रखा जाना चाहिए।

11 दिनों में मात्र 5 प्रतिशत खरीदी, 36 दिन में कैसे पूरा हो पायेगा 95 प्रतिशत लक्ष्य:बैज

रायपुर,28 नवंबर । प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार की बदनीयती से प्रदेश के किसान परेशान हैं। 160 लाख टन लक्ष्य के मुकाबले शुरुआती 11 दिनों में 5 प्रतिशत खरीदी भी नहीं हो पायी है, जबकि छुट्टी के दिनों को छोड़ कर इस खरीफ सीजन में कुल 47 दिन ही खरीदी होना है ऐसे में शेष 36 दिनों में 95 प्रतिशत लक्ष्य असंभव है। सरकार किसानों का पूरा धान खरीदना नहीं चाहती इसलिए खरीदी धीमी गति से की जा रही है। एक तरफ यह सरकार दावा करती है कि जिन किसानों ने पिछले साल धान खरीदी के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराया है उन्हें दोबारा पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रदेश के हजारों किसान ऐसे हैं जिन्होंने जिस खसरे और रकबा का पंजीयन करवाया है, पिछले साल उसी पंजीयन के आधार पर जारी टोकन से धान बेचा है उनका रकबा इस साल पोर्टल पर शून्य दिखा रहा है। कई किसानों के धान के फसल को पोर्टल पर अन्य फसल दिखाया जा रहा है। आखिर यह गड़बड़ी कर कौन रहा है? खसरा-फसल विसंगतियों, भौतिक सत्यापन की नई कवायद और खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर किसानों में असमंजस और परेशानी बनी हुई है।



प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि विगत 8 सितंबर 2026 से खाली है, पिछले ढाई महीने से सभी परीक्षाएं और साक्षात्कार स्थगित किये जा रहे है। 2023 के विधानसभा चुनाव के दौरान मोदी की गारंटी के नाम पर प्रदेश के युवाओं से वादा किया गया था कि यूपीएससी पैटर्न पर पीएससी भर्ती परीक्षा होगी, क्या यही यूपीएससी पैटर्न है? 2025 का पीएससी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू इसी के चलते अनिश्चित काल के लिये रोक दिया गया है, यह सरकार छत्तीसगढ़ के युवाओं से विश्वासघात कर रही है। 80 दिनों से पीएससी का सारा काम काज ठप्प पड़ा है। सरकार एक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं कर पा रही है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच बुलाये गये संसद के विशेष सत्र को लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं का भद्दा मजाक है। मोदी सरकार जल्दबाजी में विशेष सत्र बुलाकर ऑपरेशन लोटस व दलबदल के जरिए जुटाए गए बहुमत से संविधान संशोधन का खेल खेलना चाहती है। विपक्ष को विश्वास में लिए बिना दलबदल के दागदार बहुमत के दम पर संविधान से छेड़छाड़ करना चाहती है। कांग्रेस 2029 से महिला आरक्षण लागू करने के पक्ष में है, वर्तमान सीटों पर ही बिना किंतु परंतु के महिला आरक्षण तत्काल लागू करवाएं सरकार लेकिन जनगणना के आंकड़े आए बिना और जातिगत जनगणना को आधार बनाए बिना परिसीमन स्वीकार नहीं किया जाएगा। भाजपा सरकार लगातार संसदीय मर्यादाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है।

सोनिया गांधी की वोटर लिस्ट एंट्री पर विवाद

दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की ATR

नई दिल्ली,28 नवंबर। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी का नाम भारतीय नागरिकता मिलने से पहले मतदाता सूची में दर्ज होने के आरोपों से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में एक्शन टेकन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। शनिवार को मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने शिकायत को एक पुलिस थाने से दूसरे थाने में स्थानांतरित किए जाने पर सवाल उठाए। पुलिस ने बताया कि क्षेत्राधिकार के आधार पर शिकायत को आईपी एस्टेट थाने से तुगलक रोड थाने भेजा गया था। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि 2 सितंबर 2025 को क्षेत्राधिकार के आधार पर शिकायत आईपी एस्टेट थाने से तुगलक रोड थाने भेज दी गई थी। पुलिस की ओर से दाखिल ATR में कहा गया कि मामला आईपी एस्टेट थाने के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि, कोर्ट ने शिकायत को दूसरे थाने में भेजने की कानूनी प्रक्रिया और इसके लिए इस्तेमाल किए गए प्रावधान को लेकर स्पष्टीकरण मांगा। तुगलक रोड थाने के जांच अधिकारी ने अदालत को बताया कि वह मामले में कानूनी राय ले रहे हैं। इसके बाद सुनवाई को दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। यह शिकायत अधिवक्ता विकास त्रिपाठी ने 24 अगस्त 2025 को दाखिल की थी। इसमें आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उन्होंने भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को हासिल की थी। शिकायतकर्ता का दावा है कि उनका नाम 1980 की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जिसे 1982 में हटा दिया गया और फिर 1983 में दोबारा दर्ज किया गया। इसी आधार पर मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने की प्रक्रिया और इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों की जांच की मांग की गई है। यह शिकायत वकील विकास त्रिपाठी ने दाखिल की है। उनका आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम वर्ष 1980 की मतदाता सूची में दर्ज था, जबकि उन्हें भारतीय नागरिकता 30 अप्रैल 1983 को मिली थी। शिकायत में कथित तौर पर जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है।



...तो 50 साल तक नहीं हारेगी भाजपा

नई दिल्ली,28 नवंबर। संसद में एक बार फिर परिसीमन बिल लाए जाने से पहले पक्ष और विपक्ष ने अपनी गोटियां सेट करनी शुरू कर दी है। कई दलों में बगावत की वजह से बढ़ी हुई ताकत और विपक्ष में सेंधमारी की वजह से सरकार इस बार जरूरी संख्याबल जुटाने में कामयाबी के करीब दिख रही है। इस बीच आम आदमी पार्टी (आप) ने अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि वह पूरी ताकत से इस बिल का विरोध करने वाली है। 'आप' ना सिर्फ खुद इसके खिलाफ खड़ी है, बल्कि दूसरे दलों को भी सावधान कर रही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इसे 'बीजेपी जिताओ बिल' बताते हुए डर दिखाया है कि यदि यह बिल पास हो गया तो वह अगले 50 सालों तक नहीं हारेगी।

परिसीमन बिल पर आप ने बता दिया अपना डर

'आप' के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने परिसीमन बिल को लेकर भाजपा की नीयत पर सवाल खड़े किए और यह समझाने की कोशिश की है कि भाजपा इस तरह से सीटें बढ़ाने जा रही है जिससे वह हमेशा जीतती रहेगी। सांसद ने कहा कि 50 पर्सेंट वाले फॉर्मूले को लागू करने के बाद हिंदी पट्टी के उन राज्यों में भाजपा की ताकत बढ़ जाएगी, जहां उसका प्रभाव ज्यादा है। सांसद ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए अपनी बात विस्तार से समझाई। संजय सिंह ने कहा, 'डिलीमिटेशन बिल नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी जिताओ बिल है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसी चर्चा है कि वह कोई 50 पर्सेंट फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। अगर 50 पर्सेंट फॉर्मूला लाते हैं तो सीटें कहां कहां बढ़ेंगी। पूरे देश में बढ़ेंगी। फायदा किसको ज्यादा होगा, बीजेपी को होगा।'

जिन राज्यों में बीजेपी का ज्यादा प्रभाव है, वह चाहे यूपी हो, बिहार हो, बंगाल हो, छत्तीसगढ़, राजस्थान हो हिंदी पट्टी की जो राज्यें हैं, वहां इनकी 50 पर्सेंट सीटें बढ़ जाएंगी आराम से। फिर आप इनको अगले 50 साल तक हराते रहिए। हम लोग पहले दिन से इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है जब सीटों (लोकसभा-विधानसभा क्षेत्रों) को फिर से आकार दिया जाएगा तो भाजपा अपने हिसाब से बनाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बीजेपी जिताओ बिल है। जो जो पार्टियां बीजेपी को जितवाना चाहती हैं वो इनके साथ खड़े हो जाएं। जो इनको भविष्य में हरवाने की सोच रखती हैं वो इनके खिलाफ रहें। क्योंकि यह बीजेपी जिताओ बिल है।



अमेरिका में कुदरत का रौद्र रूप

अमेरिका में थैंक्सगिविंग (Thanksgiving) के दौरान आए भीषण और खराब मौसम ने लोगों की छुट्टियों का मजा किरकिरा कर दिया है। ग्रेट लेक्स, ओहियो वैली और पूर्वोत्तर (नॉर्थईस्ट) इलाकों में शुक्रवार को भी रुक-रुक कर बारिश, बर्फबारी और तेज हवाओं का दौर जारी रहा। तूफानी मौसम के कारण लाखों लोगों के घरों की बिजली गुल हो गई, यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ और कई जगहों पर बाढ़ व पेड़ गिरने जैसी घटनाएं सामने आईं। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक, कम दबाव का यह बड़ा सिस्टम धीरे-धीरे उत्तर-पूर्व की ओर बढ़ रहा है और रात के दौरान समुद्र की तरफ निकल जाएगा.

किसानों के फर्जी हस्ताक्षर कर हड़पी बीमा राशि,दो अधिकारी गिरफ्तार

जगदलपुर ,28 नवंबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों के नाम पर कथित फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बस्तर जिले में किसानों के फर्जी हस्ताक्षर के जरिए बीमा राशि हासिल करने के आरोप में पुलिस ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुन्ना लाल बघेल समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले में तीसरे आरोपी की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार, ग्राम जामगांव के किसानों ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि उनके नाम पर फर्जी हस्ताक्षर कर बजाज जनरल इंश्योरेंस कंपनी से बीमा राशि प्राप्त की गई। किसानों की शिकायत मिलने के बाद बुरगुम थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान कथित धोखाधड़ी में तीन लोगों की संलिप्तता सामने आई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मुन्ना लाल बघेल और अनिल सेठिया को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक, किसानों के फर्जी हस्ताक्षरों के आधार पर बीमा राशि प्राप्त कर किसानों और बीमा कंपनी के साथ धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है। इस मामले में तीसरे आरोपी गिरीश चंद सेठिया की भूमिका भी जांच में सामने आई है। वह फिलहाल फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि कथित फर्जीवाड़े में कितनी राशि का लेन-देन हुआ और कितने किसान प्रभावित हुए।



जम्मू-कश्मीर को विकसित राज्य बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती: राजनाथ

नई दिल्ली,28 नवंबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को भाजपा के 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पैदल मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें पार्टी के सैकड़ों नेताओं, चुने हुए प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। जम्मू-कश्मीर बीजेपी ने 'महापदयात्रा' का आयोजन किया। पार्टी का आरोप है कि कांग्रेस और 'इंडिया' गठबंधन लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने और लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इसल दौरान राजनाथ सिंह ने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद दुनिया की कोई भी ताकत जम्मू-कश्मीर को एक विकसित राज्य बनने से नहीं रोक सकती। उन्होंने जोर देकर कहा कि केंद्र सरकार आतंकवाद पर लगाम लगाने में काफी हद तक सफल रही है और इस क्षेत्र में अलगाववादी ताकतों का प्रभाव धीरे-धीरे कम हो रहा है। सिंह ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि वे लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठा रहे हैं और बिना किसी सबूत के चुनावी गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं।

छत्तीसगढ़ के स्मार्ट मीटर मॉडल को देशभर की बिजली कंपनियों ने सराहा

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 28 नवंबर। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा प्रदेश में स्मार्ट मीटर के प्रभावी क्रियान्वयन और डिजिटल सेवाओं की जानकारी साझा करने के उद्देश्य से देशभर की विद्युत वितरण कंपनियों का राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल दो दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचा। नॉलेज शेयरिंग एवं फील्ड विजिट कार्यक्रम के तहत पहले दिन डंगनिया, रायपुर स्थित मुख्यालय सेवा भवन में तथा दूसरे दिन अंजोरा में विशेष कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जीनस कंपनी के चीफप्रोजेक्ट मैनेजर बी.जी. दास ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से बताया कि दुर्ग रीजन के अंतर्गत दुर्ग, बालोद और बेमेतरा जिलों में अब तक 7 लाख 21 हजार 417 उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। यह कुल लक्ष्य का लगभग 86 प्रतिशत है। शेष उपभोक्ताओं के घरों में मार्च 2027 तक स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

कार्यपालक निदेशक शिरीष सेलट ने डिजिटल सेवाओं की उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि मोर बिजली एप का खपत पूर्वानुमान फीचर उपभोक्ताओं को आगामी बिजली बिल का अनुमान लगाने में मदद करता है। वहीं प्रकाश एप अधिकारियों एवं फील्ड अमले के



लिए बिजली व्यवस्था के संचालन और निगरानी में उपयोगी साबित हो रहा है। ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के माध्यम से पहुंचे विभिन्न राज्यों की विद्युत वितरण कंपनियों के प्रतिनिधियों ने छत्तीसगढ़ के स्मार्ट मीटर एवं डिजिटल सेवाओं के मॉडल की सराहना की।

इनमें वेस्ट डिस्कॉम इंदौर की जूनियर इंजीनियर शालू मोदी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सीनियर मैनेजर सुमित कुमार, बीसीईएस राजधानी पावर लिमिटेड दिल्ली की अनुराधा सिंह तथा तेलंगाना के अधीक्षण अभियंता सहित अन्य प्रतिनिधि शामिल रहे। इस अवसर पर मुख्य अभियंता ए.के. लखेरा एवं एच.के. मेश्राम, अधीक्षण अभियंता जे. जगन्नाथ प्रसाद एवं मुरारी श्रीहरि, कार्यपालन अभियंता शशांक श्रीवास्तव एवं आर.के. दानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

समाचार संक्षेप

पुलिस ने अवैध शराब मामले में 9 लोगों को किया गिरफ्तार



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 28 नवंबर। भिलाई में अवैध शराब के खिलाफपुलिस ने 6 थाना क्षेत्रों में अभियान चलाय है इस दौरान 8 प्रकरण दर्ज किए गए है। इसमें पुलिस ने 9 आरोपी को पकड़कर 256 पाव देशी-विदेशी शराब वाहन, नगदी रकम बरामद किया है। थाना में वैशाली नगर, पुरानी भिलाई, सुपेला, मोहन नगर, उतई, भिलाई नगर है। इसमें 1 कैम्प-1, 18 नंबर रोड निवासी मोहम्मद आजाद उर्फ टिल्लू, रमणगर लोढ़ीपारा, वैशाली नगर चंदन नेताम, भिलाई तीन थाना सिरसाकला टिपेन्द्र दास वैष्णव, थाना सुपेला संजय नगर राहुल उर्फ उदित तेलंग, अटल आवास उरला अमर सिंह पारधी, थाना उतई महावीर चौक, ग्राम मटंग एमेन्द्र वर्मा, सतनामी पारा, ग्राम मटंग शुभम महिपाल, भिलाई नगर थाना युवा चौक, रुआबांधा बस्ती अमन कंडरा, वार्ड 2, भाटापारा, भिलाई नगर योगेश कुमार यादव उर्फ बाब्बो को पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपियों के पास से देशी एवं विदेशी मदिरा, शराब बेचने का नगदी रकम और शराब परिवहन में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया गया है। पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया पुलिस ने बताया कि नशा के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत अवैध शराब बेचने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए सभी थाना क्षेत्र के प्रभारियों को निर्देशित भी किया गया है आगामी दिनों में भी कार्रवाई जारी रहेगी।

एक नजर

सफाई कर्मकारों और कचरा बीनने वालों का होगा पंजीयन

भिलाई, 28 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। नमस्ते योजना के अंतर्गत नगरीय निकायों में कार्यरत सीवर एवं सेप्टिक टैंक कर्मकारों तथा कचरा बीनने वाले कर्मकारों (वेस्ट पिकर्स) को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए पंजीयन प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस संबंध में कलेक्टर द्वारा आवश्यक आदेश जारी किया गया है। योजना के तहत पात्र कर्मकारों को छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत कर शासन की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया जाएगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्रम विभागीय डेटाबेस में मोबाइल नंबरों के मिलान के दौरान कुल 1532 कर्मकारों में से 730 कर्मकार पूर्व से ही छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल तथा छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत पाए गए हैं। वहीं, शेष 802 कर्मकार अपंजीकृत हैं। इन कर्मकारों का पंजीयन कराने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

हेरोइन तस्कर गिरफ्तार



भिलाई, 28 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप सरगना दीपक नेपाली का भाई से अवैध रूप से हेरोइन की तस्करी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जामुल टीआई राकेश खुटेश्वर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कुरूद रंगला पंजाब ढाबा, बस स्टैंड के पास हेरोइन (चिट्टा) की अवैध कारोबार में शामिल दो लोगों को पकड़ा गया है जिस में सुभाष मार्केट, केएलसी जोन-2, खुर्सीपार निवासी ओंकार सिंह, मौर्या कोचिंग के पास, 18 नंबर रोड, कैम्प-1 लुकेश कुमार सिंह को पकड़ा गया है इनके पास से पुलिस ने हेरोइन, मोबाइल तीन, नगद 3200, कुल संपत्ति 4.66 लाख 800 रुपए किया गया। पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि मादक पदार्थों की अवैध बिक्री, परिवहन एवं सेवन से संबंधित किसी भी गतिविधि की जानकारी दें

संविधान दिवस पर आयोजित क्विज प्रतियोगिता में कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा



भिलाई, 28 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। संविधान दिवस के अवसर पर शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला मचांदुर में संविधान आधारित क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें दुर्ग जिले के विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला चिरपोटी, घुघसीडीह, मचांदुर तथा हायर सेकेंडरी स्कूल मचांदुर के विद्यार्थी शामिल हुए। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों को अरपा, पैरी, महानदी और शिवनाथ नाम से चार समूहों में बांटा गया। डिजिटल डिवाइस के माध्यम से बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे गए। विद्यार्थियों ने स्वयं डिवाइस संचालित कर सवालों के जवाब दिए। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को संविधान, मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी देने के साथ उनका आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाना था। प्रतियोगिता में व्याख्याता खिलेश्वर चन्द्र साहू, संकुल समन्वयक प्रणव मांडरिक, कामोद ध्रुव, प्रधान पाठक पूर्णिमा साहू, दुलारी ठाकुर एवं प्रेमलता साहू ने निर्णायक की भूमिका निभाई। कार्यक्रम का संचालन संजय मानिकपुरी, कविता देवांगन एवं मिलिन्द चन्द्रा ने किया।

पिकअप वाहन से जब्त 4 करोड़ रुपए के लिए दायर सुपुर्दनामा को कोर्ट ने किया खारिज



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 28 नवंबर। खुर्सीपार पुलिस द्वारा पिकअप वाहन से जब्त किए गए चार करोड़ रुपए नकद हासिल करने के लिए दायर सुपुर्दनामा आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया न्यायालय ने प्रकरण की गंभीरता और जारी जांच को देखते हुए आवेदक को राशि सौंपने से इनकार कर दिया मामला 25 अक्टूबर की रात का है, जब खुर्सीपार पुलिस ने रायपुर-दुर्ग मुख्य मार्ग पर वाहन चेकिंग के दौरान पिकअप (सीजी 04 क्यूयू 5996) को रोककर तलाशी ली थी वाहन में सवार भावेश भाई डाभी और विष्णुदेव दुबे के पास से चार करोड़ रुपए नकद बरामद हुए थे दोनों ने रकम को जेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के व्यवसाय गुजरात के कारोबारी का दावा नहीं आया काम जब्त रकम पर गुजरात के गांधीनगर निवासी कमलेश आर. शाह ने अपना अधिकार जताते हुए 30 अक्टूबर को दुर्ग न्यायालय में सुपुर्दनामा आवेदन पेश किया था। दावे के समर्थन में उन्होंने अकोला न्यायालय का उत्तराधिकार आदेश और दिवंगत पत्नी नीना शाह की फर्म 'मेसर्स मेक टेक' के दस्तावेज प्रस्तुत कर इसे वैध व्यावसायिक लेन-देन बताया था से जुड़ा बताया था, लेकिन संतोषजनक वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके।

इस पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 106 के तहत नकदी जब्त कर आगे की जांच के लिए आयकर विभाग को सौंप दी थी। कई चरणों की सुनवाई के बाद आवेदन निरस्त सुपुर्दनामा आवेदन पर 5, 12, 20 और 23 नवंबर के बाद शुक्रवार 27 नवंबर को सुनवाई हुई अधिवक्ता राजकुमार तिवारी के अनुसार न्यायालय ने स्पष्ट किया कि प्रकरण गंभीर है और जांच अभी लंबित है इस लिए फिलहाल रकम लौटाना उचित नहीं है जांच पूरी होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

ठगी का आरोपी मुम्बई से गिरफ्तार

■ सोलर पैनल बाजार दर से कम कीमत पर उपलब्ध कराने व घरों में इंस्टॉलेशन का झांसा देकर 34 लाख रुपए ठगे थे आरोपी ने

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 28 नवंबर। सोलर पैनल बाजार दर से कम कीमत पर उपलब्ध कराने व घरों में इंस्टॉलेशन का झांसा देकर 34 लाख रुपए की ठगी करने वाले आरोपी को स्मृति नगर चौकी पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया है पुलिस ने पालघर (महाराष्ट्र) निवासी विवेक मिश्रा (27) को प्रोडक्शन वारंट पर मुंबई सेंट्रल जेल से लाकर दुर्ग न्यायालय में पेश किया, जबकि गिरोह के दूसरे आरोपी घाटकोपर पश्चिम (मुंबई) निवासी आयुष उपाध्याय (49) को गुजरात पुलिस पहले ही प्रोडक्शन वारंट पर ले जा चुकी है स्मृति नगर चौकी प्रभारी अमित अदाणी ने बताया कि पांच सितंबर 2026 को नवीन कुमार ने धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थी के अनुसार 24 जून 2026 को स्नेहा और खुद को कंपनी मैनेजर बताने वाले कमलेश पाटिल ने मोबाइल पर संपर्क किया दोनों ने स्वयं को मुंबई दो बैंकों से आरटीजीएस व आईएमपीएस के जरिए ट्रांसफर किए 34 लाख पुलिस जांच में झांसे में आकर प्रार्थी नवीन कुमार ने सामने आया कि अधिक मुनाफे के महिंद्रा बैंक के खातों से आरटीजीएस अपने बैंक ऑफबड़ौदा और कोटक व आईएमपीएस के माध्यम से कुल 34 लाख रुपए मुंबई स्थित एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के खाते में ट्रांसफर किए थे रकम मिलने के बाद नं तो पैनल की आपूर्ति हुई और न ही इंस्टॉलेशन किया गया की 'सनरुट एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड' से जुड़ा बताते हुए सस्ते दामों पर सोलर पैनल आपूर्ति और इंस्टॉलेशन का प्रस्ताव दिया साइबर सेल व बैंक खातों की जांच में विवेक मिश्रा व आयुष उपाध्याय की संलिप्तता उजागर होने पर बीएनएस की धारा 318 (4) व 3 (5) के तहत अपराध दर्ज किया गया पुलिस के अनुसार जल्द ही आयुष को भी प्रोडक्शन वारंट पर दुर्ग लाया जाएगा।



रिसाली में 3.45 करोड़ के विकास कार्यों का विधायक ललित ने किया शुभारंभ



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रिसाली, 28 नवंबर। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने शुक्रवार शाम नगर पालिक निगम रिसाली के पांच वार्डों में 3 करोड़ 45 लाख 35 हजार रुपये की लागत से होने वाले विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक ने नारियल फोड़कर निर्माण कार्यों की शुरुआत की और क्षेत्रवासियों को विकास कार्यों की सौगात मिलने पर बधाई दी। कार्यक्रम में संबंधित वार्डों के पार्षद एवं जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हाल ही में नगर पालिक निगम रिसाली क्षेत्र के नागरिकों को कई महत्वपूर्ण सौगातें दी हैं। अब 134 करोड़ रुपये की लागत से जल शोधन संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा 2 करोड़ रुपये की लागत से शहर को रोशन करने की व्यवस्था की जाएगी। जोरातराई एवं नेवई मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार भी कराया जाएगा। विधायक ने बताया कि शुक्रवार को वार्ड क्रमांक 1 तालपुरी, वार्ड क्रमांक 2 रूआबांधा उत्तर, वार्ड क्रमांक 3 रूआबांधा दक्षिण, वार्ड क्रमांक 5 एचएससीएल कॉलोनी तथा वार्ड क्रमांक 6 रूआबांधा सेक्टर में विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया है। इन कार्यों में वार्ड क्रमांक 1 का बहुप्रतीक्षित एवं आवश्यक एसटीपी निर्माण कार्य भी शामिल है। कार्यक्रम में पार्षद सविता ढवस, सारिका साहू, माया यादव, शीला नारखेड़े सहित मंडल अध्यक्ष राजू जंघेल एवं अनुपम साहू उपस्थित रहे।

ई-बस संचालन के लिए मार्गों के चयन पर आयुक्त ने मिनी बस मालिक संघ के साथ की चर्चा

भिलाई, 28 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। आयुक्त सुरुचि सिंह की उपस्थिति में मिनी बस मालिक संघ के प्रतिनिधियों के साथ शहर एवं आसपास के क्षेत्रों में ई-बस संचालन के लिए प्रस्तावित मार्गों के चयन के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में सोसाइटी द्वारा पूर्व में चयनित ई-बस मार्गों की समीक्षा करते हुए मार्गों की दूरी कम करने तथा आवश्यकतानुसार बसों की संख्या में कमी करने के सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया। इसके साथ ही जनसुविधा और यात्रियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए नए मार्गों पर भी ई-बस संचालन का प्रस्ताव रखा गया। मिनी बस मालिक संघ द्वारा दुर्ग से जालबांधा, पावर हाउस से पाटन, दुर्ग से भिंभौरी तथा भिलाई के इंडस्ट्रियल एरिया में ई-बस संचालन प्रारंभ करने का सुझाव दिया गया। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ई-बस संचालन के लिए पूर्व में चयनित सभी मार्गों का पुनः स्थल निरीक्षण किया जाए।



युवा संवाद में संवैधानिक मूल्यों नेतृत्व,राष्ट्र निर्माण पर हुई चर्चा

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

उतई, 28 नवंबर। संविधान दिवस के अवसर पर युवाओं में संवैधानिक मूल्यों, राष्ट्र निर्माण के प्रति जागरूकता एवं विकसित भारत 2047 के संकल्प को लेकर 'युवा संवाद ङ्क विकसित भारत 2047' कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पद्मश्री सम्मानित राधेश्याम बारले उपस्थित रहे। विशेष अतिथि के रूप में प्राचार्य, महिला महाविद्यालय भिलाई प्रतिभा छाया, माय भारत पर्यवेक्षक आरती मिश्रा, यूथ आइकन ढाल सिंह साहू एवं स्पोर्ट्स आइकन अनुराग चौधरी उपस्थित रहे। शुभारंभ मां सरस्वती एवं संविधान निर्माता डॉ. भीमराव अंबेडकर के चित्र पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। स्वागत उद्बोधन में माय भारत पर्यवेक्षक आरती मिश्रा ने कार्यक्रम की रूपरेखा एवं माय भारत के उद्देश्यों से अवगत कराया। यूथ आइकन ढाल सिंह साहू ने



पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से युवा संवाद विषय पर विचार व्यक्त करते हुए युवाओं की भूमिका, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक जिम्मेदारी एवं विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला।

मुख्य अतिथि पद्मश्री राधेश्याम बारले ने अपने उद्बोधन में कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।

स्ट्रीट लाइट 24 घंटे जलने से बिजली की बर्बादी

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 28 नवंबर। वैशालीनगर विधानसभा के शांतिनगर सड़क जीरो स्थित विद्युत पोल क्रमांक 15/263 में लगी स्ट्रीट लाइट पिछले 24 घंटे से लगातार जल रही है। दिन के समय भी लाइट चालू रहने से बिजली का अनावश्यक उपयोग हो रहा है और ऊर्जा की बर्बादी हो रही है। स्थानीय स्तर पर इस समस्या की ओर संबंधित विभाग का ध्यान आकर्षित करते हुए विद्युत व्यवस्था में उचित सुधार की मांग की गई है। समाजसेवी एवं वरिष्ठ नेता पंडित दिनेश मिश्रा सहित नागरिकों ने संबंधित विभाग से अपील की है कि मौके का निरीक्षण कर लाइट की तकनीकी खराबी को जल्द दूर किया जाए, ताकि बिजली की बचत हो सके और व्यवस्था सुचारू बनी रहे।

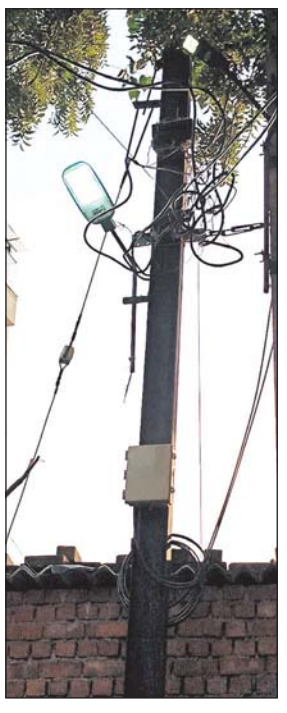

महापौर शशि सिन्हा ने किया स्कूल कक्ष का लोकार्पण

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रिसाली, 28 नवंबर। नगर निगम रिसाली की महापौर शशि सिन्हा ने वार्ड क्रमांक 17 स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मरोदा में निर्मित अतिरिक्त कक्ष का लोकार्पण किया। महापौर ने अपनी निधि से कक्ष निर्माण के लिए 10 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की थी। उन्होंने फीता काटकर नवनिर्मित कक्ष का उद्घाटन किया। इस अवसर पर महापौर शशि सिन्हा ने कहा कि शहर का विकास उनकी प्राथमिकता में हमेशा शामिल रहा है। शिक्षा के मंदिर में अध्ययनरत भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अतिरिक्त कक्ष निर्माण के लिए राशि स्वीकृत की। नए कक्ष से



विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। कार्यक्रम में महापौर परिषद के सदस्य जमुना ठाकुर सहित वरिष्ठ नागरिक एवं विद्यालय परिवार के सदस्य उपस्थित रहे।

झारखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री ने बिचपुरिया के निवास पहुंचकर की मुलाकात

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

भिलाई, 28 नवंबर। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास जी ने भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं प्रदेश कार्यसमिति सदस्य ब्रजेश बिचपुरिया जी के निवास पहुंचकर उनसे एवं उनके परिवारजनों से भेंट की। इस दौरान रघुवर दास ने ब्रजेश बिचपुरिया के साथ चाय पर राजनीतिक एवं पारिवारिक विषयों पर चर्चा की। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत-



2047 के संकल्प पर अपने विचार व्यक्त करते हुए उपस्थित कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से भारत निरंतर प्रगति के नए आयाम स्थापित कर रहा है। उल्लेखनीय है कि रघुवर दास एवं ब्रजेश बिचपुरिया के बीच लंबे समय से आत्मीय एवं स्नेहपूर्ण संबंध रहे हैं। इस विशेष अवसर पर ओबीसी मोर्चा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुंदरलाल साहू, एनजीओ प्रकोष्ठ जिला संयोजक रुद्र मूर्ति, एबीवीपी के पूर्व संयोजक पलाश घोष, युवा मोर्चा के पूर्व महामंत्री रितेश सिंह, पटरी पार मंडल अध्यक्ष मनमोहन शर्मा, दुर्ग के वरिष्ठ पार्षद एवं जिला प्रवक्ता अरुण सिंह, सक्रिय सदस्य शत्रुघ्न पंडित, युवा मोर्चा कार्यकर्ता रवि साहू, जामुल के पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रेखराम बंछोर, जामुल मंडल अध्यक्ष बंटी गुप्ता, पूर्व युवा मोर्चा अध्यक्ष सोनू यादव सहित अनेक वरिष्ठ एवं समर्पित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

एक नजर

जनपद सदस्य प्रतिनिधि विष्णु कोसले ने चंदिया पथरा में बोर खनन का किया भूमिपूजन

सिमगा 28 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। अपने जन्मदिवस को यादगार बनाते हुए जनपद सदस्य प्रतिनिधि विष्णु कोसले ने ग्राम पंचायत चंदिया पथरा में नवीन बोर खनन कार्य का विधिवत भूमिपूजन किया। इस अवसर पर ग्राम के नागरिकों एवं उपस्थित लोगों की मौजूदगी में बोर खनन कार्य की शुरुआत की गई। नवीन बोर खनन से गांव में पानी की उपलब्धता को बेहतर बनाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है। विष्णु कोसले ने अपने जन्मदिवस पर व्यक्तिगत उत्सव के बजाय जनहित से जुड़े विकास कार्य को प्राथमिकता देते हुए इस अवसर को ग्रामीणों के लिए उपयोगी बनाने की पहल की। उन्होंने कहा कि जन्मदिवस केवल खुशियां मनाने का अवसर नहीं, बल्कि समाज और क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करने का भी अवसर है। क्षेत्र के विकास, ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं और जनहित के कार्यों के लिए निरंतर प्रयास करना उनकी प्राथमिकता है। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच मेघनाथ डहरे, उपसरपंच श्री मति सीमा घीतोड़े पंच श्री मति संगीता यादव, श्री मति लल्ली यादव, श्री मति रानी बंजारे, शिव धृतलहरे, लक्ष्मण धृतलहरें सरजू निषाद ग्राम के नागरिक एवं अन्य लोग उपस्थित रहे।

11 बीटी रोड सहित 15 कार्यों के लिए 5.50 करोड़ स्वीकृत

रायपुर. 28 नवंबर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सारंगढ़ नगर पालिका में 15 कार्यों के लिए कुल पांच करोड़ 49 लाख 83 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें चार करोड़ आठ लाख 90 हजार रुपए लागत की 11 बी.टी. सड़कों, 60 लाख 10 हजार रुपए के दो सीसी रोड और 80 लाख 83 हजार रुपए के दो पुलियों के निर्माण शामिल हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से अधोसंरचना मद से ये राशि मंजूर की गई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने सारंगढ़ नगर पालिका में वार्ड क्रमांक-1 में कॉलेज रोड से जेल रोड तक बी.टी. सड़क के निर्माण के लिए 25 लाख 61 हजार रुपए और वार्ड क्रमांक-02-03 में सिविल कोर्ट से गौरव पथ अपेक्स बैंक तक बी.टी. रोड के लिए 40 लाख नौ हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। विभाग द्वारा वार्ड क्रमांक-04-05 में जनपद पंचायत कार्यालय से इंडोर स्टेडियम तक सीसी रोड के लिए 48 लाख 12 हजार रुपए एवं वार्ड क्रमांक-5 में सीसी रोड के लिए 11 लाख 98 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने वार्ड क्रमांक-7 में बी.टी. रोड के लिए 31 लाख 71 हजार रुपए तथा वार्ड क्रमांक-07-13 में ठाकुर राउर चौक से रायपुर रोड नाका नम्बर-5 तक बी.टी. रोड के लिए 47 लाख 69 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। वार्ड क्रमांक-08-09 में अटल परिसर से नंदा चौक तक बी.टी. रोड के लिए 37 लाख 87 हजार रुपए और अटल परिसर से आजाद चौक तक बी.टी. रोड के लिए 35 लाख 20 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। विभाग ने वार्ड क्रमांक-08-09-12-13 में नंदा चौक से दौलत चौक होते हुए शनि मंदिर तक बी.टी. रोड के लिए 36 लाख 15 हजार रुपए और वार्ड क्रमांक-09-10-12 में साप्ताहिक दैनिक बाजार से देवघरा चौक तक बी.टी. रोड के लिए 49 लाख 92 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं।



सिमगा 28 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। जन्मदिवस के अवसर पर आदिश जैन ने भगवान श्री 1008 भगवान महावीर स्वामी का अभिषेक किया।

वोट बचाओ, देश बचाओ' को लेकर सिमगा के ग्राम चंदेरी और दरचुरा में बूथ चौपाल आयोजित

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

सिमगा 28 नवंबर। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार लोकतंत्र की रक्षा, मतदाता सूची में पारदर्शिता और प्रत्येक पात्र नागरिक के मतदान अधिकार को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सिमगा ब्लॉक के ग्राम पंचायत चन्देरी और दरचुरा में में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के तहत बूथ चौपाल का आयोजन कर ग्रामीणों से चर्चा की गई।

कार्यक्रम में दिल्ली के पर्यवेक्षक शरद अहेर, पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर, पूर्व विधायक चैतराम साहू,प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि सुनील माहेश्वरी , पूर्व मंडी अध्यक्ष सुशील शर्मा,पूर्व विधायक चैतराम साहू वरिष्ठ नेता कुबेर यदु सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रिंकू भाटिया ने किया। शरद अहेर AIIC पर्यवेक्षक ने कहा



कि स्क्रूक की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष होनी चाहिए। किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं कटना चाहिए। लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रत्येक नागरिक के वोट की रक्षा जरूरी है।

पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि भाजपा और मोदी सरकार को चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों का जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि मतदाता सूची में पारदर्शिता रहे और किसी भी नागरिक के साथ अन्याय न हो । ये जवाबदारी सभी बूथ अध्यक्षों के साथ साथ कांग्रेस कार्यकर्ता और हम सब की है।

प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि सुनील माहेश्वरी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को चुनाव आयोग की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करनी चाहिए।उन्होंने कहा की पहले तो सिर्फ मशीन से वोट चोरी होती थी ,अब तो मतदाता सूची से भी वोट चोरी का षड्यंत्र हो रहा है। बूथ अध्यक्ष एवं कांग्रेस कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर मतदाताओं को जागरूक करेंगे।

चौपाल में वरिष्ठ नेता सुशील शर्मा,कुबेर यदु एवं राजीव पंचायती राज के जिला अध्यक्ष रमेश धृतलहरे ने भी ग्रामीणों को अपने मतदान अधिकारों के प्रति जागरूक रहने तथा मतदाता सूची में अपना नाम जांचने की अपील की । कार्यक्रम में प्रमुख रूप से मंडल अध्यक्ष श्यामलाल देवांगन, हीरालाल साहू, राजा तिवारी, अर्चना ठाकुर महिल कांग्रेस प्रदेश महामंत्री, संतोष सोनी, कमलेश

कौशल,बाबूलाल साहू,बूथ अध्यक्ष मनोहर सेन, बूथ अध्यक्ष गोलू दिवाकर, टोमन निषाद, अरविंद कौशल, मोती लाल निषाद, संतोष साहू, राहुल शर्मा,लोमान धृतलहरे,विष्णु कोसले,विक्की मानिकपुरी ,यश शर्मा, विक्की पाण्डे,शेष साहू, धनसिंह साहू, दिनेश साहू, विवेक कुर्रे,हिम्मत शर्मा, आशु साहू ,पूरण देवांगन, अमन पांडे, सोनाऊ लहरे,एवं सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण जन उपस्थित थे।

छत्तीसगढ़ में किसानों को मिल रहा देश में सर्वाधिक लाभ:मुख्यमंत्री

रायपुर, 28 नवंबर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों की खुशहाली और आर्थिक समृद्धि के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश के अन्नदाता किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने के साथ ही धान खरीदी की व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाया जा रहा है। राज्य सरकार ने इस वर्ष किसानों के हित में ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचने वाले किसानों को भी निर्धारित सीमा तक अंतर की राशि का लाभ दिया जाएगा। इससे कम उत्पादन वाले क्षेत्रों के किसानों को भी आर्थिक लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री श्री साय आज पत्रकारों से चर्चा के दौरान धान खरीदी और किसानों को दी जा रही सुविधाओं के संबंध में पूछे गए सवालों का जवाब दे रहे थे।मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ के किसानों को जिस प्रकार आर्थिक लाभ दिया जा रहा है, वैसा लाभ किसी अन्य राज्य के किसानों को नहीं मिल रहा है। हमारी सरकार किसानों की मेहनत का सम्मान करते हुए उन्हें अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर निर्णय ले रही है। धान खरीदी की व्यवस्था ऐसी हो कि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और अधिकतम सुविधाएं उन्हें घर बैठे मिल सकें, इसके लिए सरकार लगातार



प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने किसानों के हित में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ के सभी क्षेत्रों में प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान का उत्पादन नहीं होता। प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में खेती की परिस्थितियां और उत्पादन क्षमता भी अलग-अलग हैं। ऐसे में कम उत्पादन करने वाले किसानों को भी निर्धारित सीमा तक अंतर की राशि का लाभ देने का निर्णय उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं स्वयं किसान का बेटा हूं और खेती-किसानी की परिस्थितियों को भलीभांति समझता हूं। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जो किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम धान बेचते हैं, उन्हें भी 21 क्विंटल की निर्धारित सीमा तक अंतर की राशि उनके खातों में प्रदान की जाएगी। हमारी सरकार चाहती है कि प्रदेश का कोई भी किसान कम उत्पादन के कारण इस लाभ से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। किसानों को उनकी मेहनत का उचित प्रतिफल मिले, खेती लाभकारी बने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त हो, इसी उद्देश्य से सरकार नीतिगत निर्णय ले रही है।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि है। धान खरीदी से लेकर आर्थिक सहायता और सुविधाओं के विस्तार तक हर स्तर पर किसानों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जा रही है। अन्नदाता की समृद्धि ही समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव है।

करमा महोत्सव में मुख्यमंत्री ने दी 71.48 करोड़ रुपये के 694 विकास कार्यों की सौगात

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की समृद्ध जनजातीय संस्कृति और परंपराएं हमारी अमूल्य धरोहर हैं। करमा महोत्सव हमारी लोकआस्था, प्रकृति के प्रति सम्मान और सामाजिक एकजुटता का जीवंत प्रतीक है। हमारी सरकार इन गौरवशाली परंपराओं के संरक्षण एवं संवर्धन के साथ प्रदेश के दूरस्थ और जनजातीय अंचलों में विकास की नई संभावनाओं को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा संकल्प है कि विकास का लाभ हर गांव, हर परिवार और समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री श्री साय आज बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत रघुनाथनगर के शासकीय हाई स्कूल मैदान में आयोजित करमा महोत्सव को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने जिलेवासियों को 71 करोड़ 48 लाख रुपये की लागत के 694 विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 54 करोड़ 21 लाख रुपये के 672 कार्यों का भूमिपूजन एवं शिलान्यास तथा 17 करोड़ 27 लाख रुपये के 22 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने करमा देव को नमन करते हुए क्षेत्रवासियों को करमा महोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने क्षेत्र के विकास को नई गति देने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं।

सेवा सेतु के माध्यम से दो दिनों मे मिला केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र, रेलवे भर्ती परीक्षा में शामिल होने का खुला अवसर

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार, 28 नवंबर। जिले में सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से नागरिकों को शासकीय सेवाओं का लाभ समयबद्ध एवं सुगम तरीके से मिल रहा है। इसी कड़ी में तहसील कार्यालय बलौदाबाजार स्थित सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से नयापारा, तहसील लवन निवासी टिकेश्वर विश्वकर्मा को आवेदन करने के महज दो दिनों के भीतर केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ।

टिकेश्वर विश्वकर्मा, पिता श्री बलीराम विश्वकर्मा ने बताया कि उन्होंने 23 नवंबर 2026 को केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए सेवा सेतु केंद्र तहसील कार्यालय बलौदाबाजार में आवेदन प्रस्तुत किया था। आवेदन के निराकरण उपरांत 25 नवंबर 2026 को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार द्वारा प्रमाण पत्र

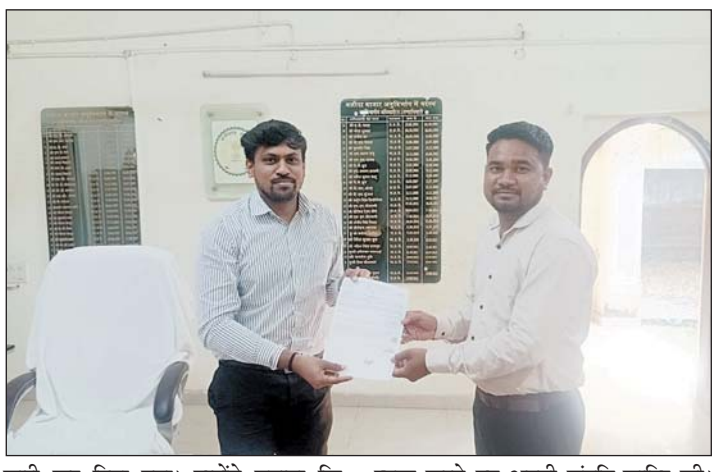

जारी कर दिया गया। उन्होंने बताया कि समय पर प्रमाण पत्र प्राप्त होने से उन्हें रेलवे भर्ती परीक्षा में शामिल होने का अवसर मिल सका। इस सुविधा के लिए उन्होंने शासन-प्रशासन एवं सेवा सेतु केंद्र के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी संतुष्टि जाहिर की। सेवा सेतु केंद्र के माध्यम से शासकीय सेवाओं का समयबद्ध निराकरण नागरिकों के लिए सुविधा और सहूलियत का माध्यम बन रहा है।

शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हाट-बाजार के लिए 1.99 करोड़ मंजूर

रायपुर. 28 नवंबर। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बेमेतरा जिले के मारो नगर पंचायत में दो कार्यों के लिए कुल एक करोड़ 99 लाख आठ हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। इनमें वार्ड क्रमांक-3 में 99 लाख नौ हजार रुपए की लागत से हाट-बाजार और वार्ड क्रमांक-7 में 99 लाख 99 हजार रुपए से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण शामिल है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने संचालनालय से इनकी मंजूरी के आदेश जारी कर दिए हैं। विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट से अधोसंरचना मद से ये राशि मंजूर की गई है।

शासकीय उच्च प्राथमिक शाला हथकली में धूमधाम से मनाया गया संविधान दिवस



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

कोंडागांव 28 नवंबर। 26 नवंबर 2026 को शासकीय उच्च प्राथमिक शाला हथकली संकुल केंद्र हासेल में संविधान दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री रामनाथ नाग जी (जनपद सदस्य) जनप्रतिनिधि एवं मर्दापाल तहसील के नायब तहसीलदार श्री विजय प्रताप सिंह जी विशिष्ट अतिथि, साथ ही शाला प्रबंधन समिति हथकली के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, पालक, गण तथा शाला के सभी शिक्षक उपस्थित रहे, सर्व प्रथम मुख्य अतिथि द्वारा श्री नाग जी द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के छाया चित्र का पूजन अर्चन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया , कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक का केंद्र रहा शाला के वशिष्ठ एवं नवाचारी शिक्षक श्री रमेश कुमार अनंत द्वारा कबाड़ से जुगाड निर्मित बाबा साहब अम्बेडकर का कट आउट जो पूर्ण रूप से कार्डबोर्ड खड्डा से बनाया गया था, साथ ही भारतीय संविधान का प्रारूप भी कबाड़ से जुगाड के माध्यम से बना कर शिक्षक द्वारा नवाचार शाला में किया गया , ये दोनों गतिविधियां को अतिथियों और शाला के बच्चों के बीच आकर्षक का केंद्र रहा। मुख्य अतिथि श्री रामनाथ नाग ने शाला हथकली के बच्चों को संविधान के बारे में बताया गया तथा संविधान के रास्ते में चलने की बात कहा , शाला के बच्चों द्वारा शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुति दी गई, जो सभी को मंत्र मुग्ध कर दिया इस अवसर पर पालक गण , स्व सहायता समूह के महिलाए snc सदस्य, उपस्थित रहे शाला के प्रधान अध्यापक श्री पुरुषोत्तम राम साहू जी ने 26 नवंबर 1946 को संविधान बनने से लागू करने एवं महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहनता से प्रकाश डाला, शिक्षक श्री अनंत जी बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर स्व रचित कविता बच्चों को सुनाया कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को बिस्किट मिठाई खिलाया गया साहू सर द्वारा आभा सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया, इस प्रकार कार्यक्रम का समापन किया गया

प्रशासन की टीम ने बिचौलियों से 80 कट्टा अवैध धान किया जब्त



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार 28 नवंबर। जिला प्रशासन द्वारा बिचौलियों पर कड़ी निगरानी की जा रही हैं। इसी कड़ी मे कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर शुक्रवार को प्रशासन की टीम ने तहसील पलारी मे बिचौलियों पर कार्यवाही करते हुए 80 कट्टा अवैध धान जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम पलारी दीपक निकुंज के नेतृत्व मे तहसील पलारी अंतर्गत ग्राम देवसुंदरा मे थानुराम वर्मा श्री राम ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान में 32 कट्टा एवं ग्राम दतान मे पूरनलाल साहू, अमृत ट्रेडर्स के प्रतिष्ठान में 48 कट्टा धान का जब्ती प्रकरण तैयार कर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के तहत कार्यवाही किया गया। जिला प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया है कि कोचिये और बिचौलिए पर कड़ी नजर रखी जा रही है।उपार्जन केंद्रों मे अवैध धान खापाने की कोशिश पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

धान का कम उत्पादन होने पर भी किसानों को 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से मिलेगी अंतर राशि

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार, 28 नवंबर। छत्तीसगढ़ की सुशासन सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लगातार महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों से किसानों में खुशी का माहौल है।

ग्राम पौसरी निवासी किसान श्री गोविंद प्रसाद वर्मा ने प्रदेश सरकार की किसान हितैषी नीतियों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल तक धान की खरीदी की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य दिलाने की दिशा में सरकार की यह पहल सराहनीय है।

गोविंद ने विशेष रूप से कृषक उन्नति योजना के तहत लिए गए निर्णय की सराहना करते हुए बताया कि जिन किसानों का धान उत्पादन प्रति एकड़ 21 क्विंटल से कम हुआ है, उन्हें भी 21 क्विंटल के मान से अंतर की राशि का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का यह निर्णय कम उत्पादन वाले किसानों के लिए बड़ी राहत है। इससे किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी और खेती-किसानी के प्रति उनका विश्वास और मजबूत



होगा।

उन्होंने बताया कि उनके पास लगभग 4 एकड़ कृषि भूमि है। उन्होंने कहा कि किसान दिन-रात मेहनत करके फसल तैयार करता है। ऐसे में सरकार द्वारा किसानों की समस्याओं को समझते हुए उनकी उपज का बेहतर मूल्य सुनिश्चित करना और कम उत्पादन की स्थिति में भी आर्थिक सहायता देना सराहनीय कदम है।

किसान गोविंद ने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सुशासन सरकार सदैव किसानों के हित में काम कर रही है। सरकार के किसान हितैषी निर्णयों से किसानों को आर्थिक संबल मिल रहा है। उन्होंने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए कहा कि किसानों की मेहनत और उनकी समस्याओं को समझकर लिए जा रहे ऐसे निर्णय वास्तव में प्रशंसनीय हैं।

बाल विवाहमुक्त पंचायत बनाने गांव-गांव में उठ रही आवाज

पंचायतों ने लिया बाल विवाहमुक्त ग्राम बनाने का संकल्प

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

बलौदाबाजार, 28 नवंबर। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी अतुल परिहार के मार्गदर्शन तथा प्रभारी जिला बाल संरक्षण अधिकारी दीपक राय के नेतृत्व में जिला बाल सरक्षण इकाई एवं चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम द्वारा बाल विवाह मुक्त बनाने के उद्देश्य से बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के ग्राम पंचायत लटुआ, मोहतरा, चॉदन, कोसमंदी, खैरताल, परसाभदेर, रवान, झोंका, गिन्दोला एवं छेरकापुर में विशेष ग्रामसभा के दौरान ग्रामीणों को जागरूक किया। बाल विवाह की रोकथाम, कम उम्र में विवाह से होने वाले शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक दुष्परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की गई। अभियान के माध्यम से ग्रामीणों की बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति



के खिलाफ जागरूक करते हुए इसे रोकने के लिए सामुहिक जिम्मेदारी निभाने का संकल्प दिलाया गया।

जनभागीदारी से बनेगा बाल विवाह मुक्त गांव : जिला बाल सरक्षण इकाई एवं चाइल्ड लाइन की संयुक्त टीम के माध्यम से ग्रामीणों को विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़के की 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह कराना कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की जानकारी देते हुए लोगों से ऐसे मामलों की सूचना संबंधित विभाग एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर देने की अपील की गई। विशेष ग्रामसभाओं में पंचायत प्रतिनिधियों, आंगनबाडी एवं आशा कार्यकर्ताओं, स्वसहायता समूहों किशोर-किशोरियों तथा स्कूल-कॉलेज के प्रतिनिधियों ने भागीदारी निभाई। ग्रामीणों ने बाल विवाह नहीं करने और न ही अपने आसपास होने देने की सामूहिक शपथ ली। अभियान का उद्देश्य केवल जागरूकता तक सीमित न रहकर प्रत्येक गांव में जनभागीदारी के माध्यम से बाल विवाह के विरुद्ध मजबूत सामाजिक वातावरण तैयार करना है।

राइस मिलों में खाद्य विभाग ने दबिश देकर 6.83 करोड़ रुपए के धान की कमी पकड़ी

बलौदाबाजार, 28 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देशानुसार जिले मे प्रशासन एवं खाद्य विभाग की टीम द्वारा कोचियो एवं रईस मिल की जांच की जा रही हैं। इसी कड़ी मे गुरुवार को खाद्य विभाग की टीम द्वारा विकासखण्ड सिमगा के राईस मिलो मे छापामार कार्यवाही की गई जिसमें दो राईस मिलों मे 6.83 करोड़ रुपए के 28871 क्विंटल धान की कमी पकड़ी गई।

जिला खाद्य अधिकारी पुनीत वर्मा ने बताया कि : सिमगा विकासखंड अंतर्गत ग्राम मोहरा स्थित श्री श्याम राइस इंडस्ट्रीज एवं सलूजा इंडस्ट्रीज में टीम के द्वारा दबिश दी गयी। श्री श्याम राइस इंडस्ट्रीज मोहरा मे ?4,58,44,414 कीमत के 19,351.80 क्विटल धान कम पाया गया।इसी प्रकार सलूजा इंडस्ट्रीज में ? 22551553 मुल्य के 9519.44 क्विंटल धान की कमी पायी गयी । श्री श्याम राईस इंडस्ट्रीज द्वारा नागरिक आपूर्ति निगम व भारतीय खाद्य निगम में 14324.59 क्विंटल चांवल जमा करना बाकि है परंतु मिल के गोदाम व मिल परिसर मे भौतिक रूप से केवल 190.50 क्विंटल चावल और 1,541.60 क्विंटल धान उपलब्ध पाया गया ।इसी प्रकार सलूजा इंडस्ट्रीज के भौतिक सत्यापन में सिर्फ3.60 क्विंटल धान व 12.0 क्विंटल चांवल उपलब्ध पाया गया जबकि उक्त मिल को 6459.77 क्विंटल चावल नागरिक आपूर्ति निगम व भारतीय खाद्य निगम में जमा करना शेष है।कमी पाए गए धान के सबंध में श्री श्याम राईस इंडस्ट्रीज मोहरा के संचालक राहुल अग्रवाल व सलूजा इंडस्ट्रीज के संचालक श्री दारा सिंह सलूजा द्वारा किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका ।दोनों राईस मिल संचालकों को अनेक बार चावल जमा करने निर्देशित करने उपरांत भी उनके द्वारा चावल जमा नही किया जा रहा था ।

विपक्ष का कमजोर होना एक मौका तो है सरकार के लिए

विपक्ष कमजोर होता है तो उसका फायदा सत्तारूढ़ दल उठाता ही है। वह ऐसे मौके पर अपना वह काम सबसे पहले कर लेना चाहता है जो विपक्ष के मजबूत होने पर नहीं हो सका है या हो ही नहीं सकता।यही वजह है वर्तमान में विपक्ष के बिखराव का सरकार फिर एक बार फायदा उठाने के लिए संसद का विशेष सत्र ३० नवंबर का बुलाया।संसद के विशेष सत्र को बुलाया ही इसलिए गया है कि जो काम पिछले संसद सत्र में नही हुआ था,जिसके लिए संसद सत्र को स्थगित नहीं किया गया था। इस दौरान विपक्ष में बिखराव बढ़ा है तथा जो लोग पिछली बार विरोध में थे, उनके सुर भी बदले हैं।यही वजह है कि मोदी कैबिनेट ने प्रस्तावित परिसीमन विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि का प्रस्ताव है, जिससे अधिकतम सीटें 850 हो सकती हैं।

संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के अनुसार, केंद्र सरकार ने संसद के दोनों सदनों की संक्षिप्त बैठक बुलाई है। इस बैठक में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन विधेयक दोबारा पेश किए जाने की चर्चा है, ताकि 2029 से पहले महिला आरक्षण लागू हो सके।

30 नवंबर को लोकसभा और 2 दिसंबर को राज्यसभा की बैठक में जरूरी सरकारी काम-काज निपटाने का जिक्र है। यानी प्रस्तावित शेड्यूल के हिसाब से लोकसभा अधिकतम 4 दिन और राज्यसभा 2 दिन चल सकती है।इस दौरान मोदी सरकार वह काम इस बार आसानी से कर सकती है जो काम वह संसद के पिछले सत्र में नहीं कर सकी थी।पिछले संसद से अब तक देश में राजनीतिक समीकरण बदल गए हैं, विपक्ष का बिखराव बढ़ा है, कांग्रेस ने कई आयोजन के जरिए विपक्ष को अपने साथ जोड़े रखने का प्रयास किया लेकिन वह सफल नहीं हो पाई है। क्योंकि विपक्ष के जो मजबूत नेता थे वह कमजोर हो गए हैं।कई क्षेत्रीय दलों में हुई टूट, पालाबदल और नए गठबंधनों ने विपक्ष की ताकत कम हुई है और एनडीए का संख्याबल बढ़ा है।

संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र में परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने के लिए एनडीए को दो-तिहाई बहुमत की जरूरत है। 540 सदस्यों वाली लोकसभा में 320 सांसदों वाले एनडीए को पूर्ण उपस्थिति में 40 अतिरिक्त वोटों की जरूरत होगी। यह आंकड़ा डीएमके, वाईएसआरसीपी और एनसीपी शरद पवार के समर्थन या सपा के वोटिंग से दूर रहने पर निर्भर करेगा।बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए के सामने एक नई संख्यात्मक चुनौती खड़ी हो गई है। संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र के दौरान, सरकार परिसीमन से जुड़े महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करने की योजना बना रही है, जिसे लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

लोकसभा में सत्ताधारी गठबंधन के पास लगभग 320 सांसद हैं, इस सत्र में एनडीए का लक्ष्य 360 वोटों का जुगाड़ करना है तो इस का एक तरीका यह हो सकता है कि उसे डीएमके के 22 सांसदों, एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के 8 सांसदों, वायएसआरसीपी के 4 सांसदों और 6 निर्दलीय या छोटी पार्टियों के सदस्यों का समर्थन मिल जाए। इन सबको मिलाकर, एनडीए की मौजूदा 320 की संख्या में 40 प्लस हो जाएंगे।एक दूसरा तरीका यह हो सकता है कि अगर समाजवादी पार्टी के 37 सांसद वोटिंग से दूर रहते हैं यानी वोट नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में, सदन में मौजूद और वोट देने वाले सदस्यों की संख्या 540 से घटकर 503 रह जाएगी, जिससे दो-तिहाई बहुमत के लिए जरूरी वोटों की संख्या 336 हो जाएगी। एनडीए के पास पहले से ही 320 सांसद हैं, इसलिए सरकार को 16 और वोटों की जरूरत होगी। एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के 8 सांसदों, वायएसआरसीपी के 4 सांसदों और 4 निर्दलीय सदस्यों का समर्थन मिलने पर कुल संख्या 336 तक पहुंच जाएगी।

सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है तो इससे समझा जा सकता है कि सरकार को संसद में जो भी बिल पारित कराने हैं, उसके लिए उसने विपक्ष के सहयोग करने वाले दलों से बात कर ली है और उनसे आश्वासन मिल गया है कि सरकार अगर उनके मुताबिक बिल में बदलाव करती है वह सहयोग करेंगे।यही वजह है सरकार ने इस बार से परिसीमन बिल में सभी राज्यों में लोकसभा सीटों की संख्या 50प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव किया है।कई विपक्षी दल खुलकर सरकार का समर्थन करते हुए नहीं दिखना चाहेंगे तो वह सरकार का सहयोग संसद में अनुपस्थित रहकर कर सकते हैं।सरकार ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिल पारित कराने के लिए संख्या बल का जुगाड़ कर लिया है, इससे उम्मीद की जा सकती है कि वह जो काम पिछले सत्र में नहीं कर पाई थी,इस विशेष में वह आसानी से कर लेगी।

विश्लेषण

परिसीमन-महिला आरक्षण पर फिर आर-पार, विपक्ष में दरार

स्वदेश कुमार ,लखनऊ



संसद एक बार फिर उस सवाल पर लौट रही है, जिस पर अप्रैल में सरकार को अपनी पहली बड़ी संसदीय हार झेलनी पड़ी थी। लोकसभा 30 नवंबर और राज्यसभा 2 दिसंबर को बैठेगी और कार्यवाही 3 दिसंबर तक चलेगी। सरकार इसे आवश्यक सरकारी कामकाज बता रही है, लेकिन माना जा रहा है कि वह 131वां संविधान संशोधन विधेयक, 2026 फिर लाएगी, जिसमें लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 850 करने का प्रस्ताव है। आज 27 नवंबर को मोदी कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा भी हुई। अप्रैल का घटनाक्रम इस पूरी बहस की कुंजी है। तब सरकार ने 16 से 18 अप्रैल तक विशेष सत्र बुलाया था और 17 अप्रैल को यह संशोधन लोकसभा में 298 के मुकाबले 230 मतों से गिर गया, जो दो-तिहाई बहुमत से काफी कम था। उस दिन सदन में मौजूद 528 सदस्यों के हिसाब से जरूरी आंकड़ा 352 था। अंतिम क्षणों में गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के लिए 50 फीसदी आनुपातिक बढ़ोतरी को बिल में जोड़ने की पेशकश की, पर विपक्ष अपने रुख पर कायम रहा। इसके बाद सरकार ने परिसीमन और केंद्रशासित प्रदेशों से जुड़े दोनों साथ वाले विधेयक वापस ले लिए। इस विवाद की जड़ 2023 के कानून में है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, यानी 128वां संशोधन, लोकसभा में 454-2 के भारी बहुमत से पारित हुआ था। राज्यसभा में उसे सभी 214 सदस्यों का समर्थन मिला। पर कानून में पेंच यह था कि आरक्षण जनगणना के बाद होने वाले परिसीमन पर आधारित है, और मौजूदा जनगणना की संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 है। इसलिए 2029 के आम चुनाव से पहले उस आधार पर परिसीमन पूरा होने की संभावना कम मानी जाती है। सरकार का तर्क था कि अगली जनगणना और परिसीमन में समय लगेगा और महिलाओं की भागीदारी टलेगी, इसलिए 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाए। यही प्रस्ताव विपक्ष को खटका। विपक्ष की आपत्ति दो बातों पर है। पहली, शशि थरूर ने कहा था कि महिला कोटे को परिसीमन से जोड़ना महिलाओं की आकांक्षाओं को बंधक बनाना है। दूसरी, दक्षिणी राज्यों को डर है कि उनका प्रभाव घटेगा और बदलाव का फायदा उत्तर में मजबूत भाजपा को मिल सकता है। कांग्रेस का कहना है कि वह आरक्षण के पक्ष में है, पर परिसीमन और सीटें बढ़ाना अनिवार्य बनाने पर उसे आपत्ति है। पी. चिदंबरम का सुझाव है कि अनुच्छेद 334 हटा दिया जाए तो आरक्षण तुरंत लागू हो सकता है।खैर, तमाम किंतु-परंतु के बीच मोदी सरकार के सामने अब असली लड़ाई संख्या बल की है। 540 की प्रभावी सदस्य संख्या में बिल पास कराने के लिए 361 वोट चाहिए, जबकि अप्रैल में एनडीए को 298 मिले थे। एनडीए के पास अभी करीब 320 सांसद हैं और सरकार की नजर डीएमके के 22 और एनसीपी (शरद पवार) के आठ सांसदों पर है। इन दोनों को जोड़ने पर भी आंकड़ा 355 तक पहुंचता है, यानी पांच कम। इसलिए वाईएसआरसीपी, जेएमएम, वीसीके और आरएलपी जैसे छोटे दलों से बातचीत चल रही है और कुछ विपक्षी सांसदों की गैरहाजिरी की भी उम्मीद है। बहरहाल, कयास यह लगाए जा रहे हैं कि मोदी सरकार को लोकसभा में 41 और राज्यसभा वोट कम पड़ रहे हैं, जबकि राज्यसभा में एनडीए के 142 सदस्य हैं और 161 चाहिए, यानी 19 की कमी। आंकड़ों का यह अंतर अलग-अलग गणना का नतीजा हो सकता है, पर दोनों में कमी साफ है। इस समय डीएमके की शर्तें इस पूरे गणित का केंद्र हैं। पार्टी उसी सूरत में समर्थन की बात कर रही है, जब तमिलनाडु का करीब 7.2 फीसदी हिस्सा सुरक्षित रहे। वह 1971 की जनगणना पर आधारित रोक को 25 साल और बढ़ाने और ऐसे सुरक्षा उपाय बिल के पाठ में ही शामिल करने की मांग भी कर रही है। सुप्रिया सुले ने भी बिल देखकर रुख तय करने की बात कही है और सभी राज्यों में 50 फीसदी की समान बढ़ोतरी पर समर्थन के संकेत दिए हैं। सरकार के लिए असली चुनौती इन गारंटियों को कानूनी शक्ल देना है, क्योंकि अप्रैल में विपक्ष ने सवाल उठाया था कि ऐसे सुरक्षा उपाय मूल बिल में क्यों नहीं थे। उधर, सियासी बयानबाजी की धार तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि महिलाओं को न्याय दिलाने से कोई ताकत नहीं रोक सकती और हार के लिए एक विपक्षी दल को जिम्मेदार ठहराया। अप्रैल में तो उन्होंने कांग्रेस, डीएमके, सपा और टीएमसी पर आरोप लगाते हुए इसकी तुलना भ्रूण हत्या से कर दी थी। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता जयराम रमेश इसे संविधान पर हमला बता रहे हैं और मनीष तिवारी ने सवाल उठाया कि विशेष सत्र को नियमित शीतकालीन सत्र का विकल्प नहीं बनाया जाना चाहिए। एनसीपी (सपा) ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया है। विपक्ष की एकजुटता पर सवाल भी उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ दल बिल के विवादित प्रावधानों में बदलाव चाहते हैं और सुर अलग-अलग दिख रहे हैं। इसके बावजूद सपा, टीएमसी और कांग्रेस जैसे बड़े दलों के रुख से लगता है कि पुराना स्वरूप दोहराया गया तो नतीजा भी पुराना हो सकता है। अब सवाल यह है कि पांच राज्यों के चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में फरवरी-मार्च 2027 में चुनाव होने हैं और पंजाब को छोड़कर चारों में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं। सीधा असर परिसीमन का नहीं होगा, क्योंकि 2027 की शुरुआत का विधानसभा चुनाव मौजूदा नक्शे पर ही लड़ा जाएगा। असर नैरेटिव का होगा। भाजपा हार को महिला प्रतिनिधित्व पर जनमत संग्रह की तरह पेश कर रही है, ताकि जाति और क्षेत्र से परे महिलाओं का एक वर्ग साध सके। बिल पास हुआ तो वह इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में महिला मतदाताओं के बीच भुनाएगी। गिरा तो विपक्ष ने फिर रोका महिला आरक्षण बिल का अभियान और तेज होगा। इस सबके बीच विपक्ष के लिए जोखिम भी है और मौका भी। उसने 2023 में आरक्षण के पक्ष में वोट दिया था और अब परिसीमन के तरीके पर सवाल उठा रहा है। यह तर्क पंजाब जैसे राज्य में असर कर सकता है, जहां अकाली दल ने सभी राज्यों के लिए समान 50 फीसदी बढ़ोतरी के साथ दोनों बिल पारित करने की मांग की है। पर इन मुद्दों की पेचीदगी आम मतदाता तक पहुंचाना कठिन है, जबकि महिला विरोधी का आरोप सरल संदेश है। इसलिए चुनावी असर का बड़ा हिस्सा इस पर निर्भर करेगा कि सरकार संशोधित बिल में डीएमके जैसे दलों की चिंताएं दर्ज करती है या नहीं। आज की तारीख में मतदाताओं पर प्रभाव का कोई ठोस सर्वे नहीं है, इसलिए इसे अनुमान ही मानना चाहिए।

कट रहे जंगल

लेखक - पं. अश्विनी कुमार मिश्रा

सुबह की पहली किरण अब,
शाखों से छनकर नहीं आती,
ठंडी हवा के झोंके भी,
अब आँगन को सहलाते नहीं।

जो कभी देते थे छाँव घनी,
थके-हारे राही को अपनाकर,
आज उन्हीं के ठूँठ खड़े हैं,
खामोशी का बोझ उठाकर।

धरती की कोख उजाड़ रहे हैं,
कंक्रीट के ऊँचे सपनों में,
भूल गए हैं साँसें कहाँ से,
आती थीं सूखे पत्तों में।

चिड़ियों के चहचहाने का,
अब बस एक ही राग बचा है,
जहाँ कभी था हरा समंदर,
वहाँ धूल और राख बचा है।

बादल भी रूठ कर चलते हैं,
जब ज़मीन से नाता टूटता है,
सूखी नदियों के किनारों पर,
हर मौसम बेरहम छूटता है।

यदि आज न जागे हम सब तो,
कल का सूरज भी झुलसाएगा,
एक-एक कर हरियाली खोकर,
इंसान खुद को ही खो पाएगा।

आओ फिर से जड़ें जोड़ लें,
मिट्टी से, हवा से, हर डाली से,
बचा लें जो बाकी है अभी,
यह अपनी प्यारी हरियाली।

विज्ञान

भारतीय वैज्ञानिकों को संसाधन और सम्मान कब मिलेगा?

मनोज कुमार अग्रवाल

भारतीय वैज्ञानिकों को बेहतर शोध के लिए उचित अवसर, स्वायत्तता और पेशेवर सम्मान की आवश्यकता लंबे समय से चर्चा का विषय रही है। जहाँ एक ओर देश में नई शोध योजनाएँ शुरू की जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर कार्य-संस्कृति और संसाधनों को लेकर चुनौतियाँ भी सामने आती हैं।

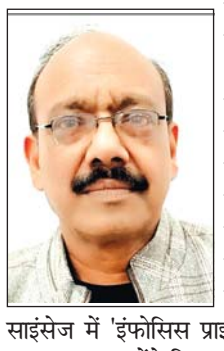

हमारे विद्वानों की श्रृंखला में ताजा नाम बेंगलुरु के मैथमैटिशियन 'ऋद्धि प्रतिम बसु' का जुड़ा है जिन्हें उनके द्वारा 'प्रोबेबिलिटी थ्योरी' में मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने, दशकों पुरानी स्लो-बॉन्ड प्रॉब्लम सुलझाने, रैंडम ग्रोथ और स्टैटिस्टिकल फिजिक्स पर उनके काम के लिए मैथमैटिकल साइंसेज में 'इंफोसिस प्राइज-2026' मिला है। इस पहेली को सुलझा कर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि एक प्वाइंट पर थोड़ी सी भी रुकावट पूरे सिस्टम में फ्लो को धीमा कर सकती है।

एक अध्ययन के अनुसार कोलकाता के रहने वाले ऋद्धि प्रतिम बसु ने स्टैनफोर्ड से जुड़ने से पहले यू.सी. बर्कले से अपनी पीएच. डी. पूरी की। उनकी इस उपलब्धि ने भारत के महान सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ 'सत्येंद्र नाथ बसु' (बोस) (1894-1974) की याद ताजा कर दी है जिनकी प्रतिभा का दुनिया ने लोहा तो माना।

आपको बता दें कि 'क्वांटम मैकेनिक्स और सांख्यिकी' के क्षेत्र में उनका योगदान अतुलनीय है। वर्ष 1924 में कोलकाता विश्वविद्यालय में पढ़ाते समय' सत्येंद्र नाथ बोस' ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण शोध-पत्र लिखा। इसमें उन्होंने क्लासिकल भौतिकी की मदद लिए बिना, प्लांक के क्वांटम रेडिएशन नियम को व्युत्पन्न किया।

उन्होंने अपना शोध-पत्र प्रसिद्ध वैज्ञानिक' अल्बर्ट आइंस्टीन' को भेजा, जिन्होंने इसके महत्व को पहचाना, इसका जर्मन भाषा में अनुवाद किया और इसे प्रकाशित करवाने में 'सत्येंद्र नाथ बोस' की सहायता की। इन दोनों के संयुक्त कार्य ने' बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी की नींव रखी और बोस-आइंस्टीन कंडेनसेट' पदार्थ की पांचवीं अवस्था के अस्तित्व की भविष्यवाणी की।

भौतिक विज्ञानी 'पॉल डिराक' ने 'सत्येंद्र नाथ बोस' के सम्मान में 'बोसोन' नाम रखा था, ये सब-एटॉमिक कणों का एक वर्ग है जिनका स्पिन पूर्णांक होता है इनमें फोटोन और हिग्स बोसोन शामिल हैं।

बर्न में अल्बर्ट आइंस्टीन के घर में सत्येंद्र (बोस) की तस्वीरें, उनके शोध-पत्र आदि मौजूद हैं।

इसे विडम्बना ही कहा जाएगा कि ' सत्येंद्र नाथ बोस' के काम पर आधारित शोध के लिए दूसरे लोगों को विज्ञान के सबसे बड़े 'नोबेल पुरस्कार' दिए गए, लेकिन स्वयं 'सत्येंद्र नाथ बोस' को इसके लिए 4 बार मनोनीत किए जाने के बावजूद यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन्हें नहीं दिया गया।

उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी खोज को मान्यता मिली तो नोबेल पुरस्कार चयन समिति ने यह कह कर देने से इन्कार कर दिया कि वे मृतक को पुरस्कार देते ही नहीं।

लेकिन क्या हम अपने वैज्ञानिकों का उतना सम्मान करते हैं, जितना हमें करना चाहिए? क्या कहीं भी हमारे वैज्ञानिकों की कोई प्रतिमा है? क्या भारत के महान वैज्ञानिकों के लिए एक दिन भी समर्पित नहीं कर सकते ? हम जो आर्यभट्ट जैसे महान विचारकों की बात करते हैं, भारत की सर्वप्रथम विश्व को शून्य देने की बात करते हैं, हमें अपने महान वैज्ञानिकों का सम्मान भी करना चाहिए। शायद समर्थन की कमी के कारण ही, भारतीय वैज्ञानिकों में से केवल डॉ. सी.वी. रमन को ही 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला।

ऐसा नहीं है कि भारत में महान प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की कमी है, हमारे वैज्ञानिकों ने हर क्षेत्र-भौतिकी, इंजीनियरिंग, अंतरिक्ष और जीव विज्ञान में महत्वपूर्ण आविष्कार और खोजें की हैं, जैसे जगदीश चंद्र बोस, सुब्रह्मण्यन, चंद्रशेखर, सर एम. विश्वेश्वरैया, येल्लाप्रगडा सुब्बाराव आदि। ऐसी भारतीय महिला वैज्ञानिकों की भी लंबी कतार है, जैसे अन्ना मणि, असीमा चटर्जी, कमला सोहोनी, राजेश्वरी चटर्जी, इंदिरा हिंदुजा, अनेकों और भी।

हमारे वैज्ञानिक नासा में जाते हैं और दुनिया भर के देशों में काम करते हैं। नासा के नाम से हमारे मन में कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स का नाम आता है, पर क्या हम जानते हैं कि कमलेश लुल्ला नासा जॉनसन स्पेस सेंटर में पृथ्वी अवलोकन के मुख्य वैज्ञानिक हैं? शर्मीला भट्टाचार्य वर्तमान में नासा एम्स रिसर्च सैंटर में एस्टेरोवायोनिक्स की मुख्य वैज्ञानिक के रूप में काम कर रही हैं। अश्विन वासवडा कैलिफोर्निया में नासा की जैट प्रोपल्शन लैबोरेट्री में एम.एस.एल. डिप्टी प्रोजैक्ट साइंटिस्ट के अहम पद पर हैं। अश्विन नासा के सबसे महत्वाकांक्षी मिशन 'मार्स क्यूरियोसिटी रोवर' के भी एक महत्वपूर्ण सदस्य हैं।

तो हम अपने ही देश में उन्हें उनका बनता सम्मान क्यों नहीं देते ? हम जो शुरू से ही गणित और विज्ञान के क्षेत्र में स्वयं को विश्व में अग्रणी मानते आ रहे हैं, क्या अब हमारा विज्ञान की ओर रुझान कम हो गया है ?

यदि हम अपने विद्वानों को प्रोत्साहित करते या अपने प्राचीन विद्वानों के 'योगदान को याद रखते तो न जाने और कितनों को यह पुरस्कार मिल सकता था। निश्चय ही यह एक महान उपलब्धि है, परंतु आज यह बात कितने भारतीयों को मालूम है कि हमारे वैज्ञानिक कितने प्रतिभाशाली थे और हैं।

ध्यान रहे कि कई शोध संस्थानों में वैज्ञानिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता के बजाय प्रशासनिक नियंत्रण और पद के आधार पर सम्मान मिलने की शिकायतें सामने आती रही हैं।

बेहतर अवसरों, कार्य-वातावरण और सम्मान की कमी के चलते कई शोधकर्ता विदेश जाते हैं या देश के संस्थानों से इस्तीफा देते हैं।

कई विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिकों को लंबे समय तक जटिल विषयों पर काम करने, असफलता से सीखने की छूट और केवल कागजी मानकों से परे हटकर गुणवत्तापूर्ण काम के आधार पर आंका जाना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन , अनुसंधान, विकास और नवाचार योजना, रामानुजन फेलोशिप और इनसपायर जैसी पहलों के माध्यम से शोध को बढ़ावा और वित्तपोषण दिया जा रहा है।

होमी जहांगीर भाभा, चंद्रशेखर वेंकटरमन, विक्रम साराभाई और जगदीश चंद्र बोस जैसे वैज्ञानिकों के योगदान ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा और विज्ञान के क्षेत्र में भारत को मजबूत पहचान दिलाई है। इनके योगदान को प्रेरणा समझ कर आगे बढ़ने की जरूरत है।

चर्चित मुद्दा

भारतीय खाद्य संस्कृति पर आघातों से सुप्रीम कोर्ट चिंतित

ललित गर्ग



भारत की पहचान केवल उसकी आध्यात्मिकता, विविधता और संस्कृति से नहीं, उसकी रसोई से भी होती है। हमारी रसोई में स्वाद के साथ स्वास्थ्य, ऋतु के साथ संतुलन और भोजन के साथ संस्कार जुड़े रहे हैं। दादी-नानी के हाथों का भोजन केवल पेट भरने का साधन नहीं था, वह परिवार की सेहत की पहली पाठशाला था। दाल, बाजरा, ज्वार, रागी, हरी सब्जियां, मौसमी फल, छाछ, अंकुरित अनाज, मसालों का संतुलित उपयोग और घर का ताजा भोजन भारतीय जीवन-पद्धति की ताकत रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ दशकों में हमारी थाली धीरे-धीरे बदल गई है। स्वाद के नाम पर बाजार ने हमारी रसोई में प्रवेश किया और सुविधा के नाम पर पैकेट ने घर की कड़ाही को पीछे धकेलना शुरू कर दिया। इसी बदलती खाद्य संस्कृति के बीच सुप्रीम कोर्ट का हालिया निर्देश एक महत्वपूर्ण चेतावनी की तरह सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने खाद्य पैकेटों पर फ्रंट-ऑफ-पैक पोषण लेबलिंग को मजबूत करने का निर्देश देते हुए कहा है कि अधिक शुगर, सैचुरेटेड फैट और नमक वाले उत्पादों पर अलग-अलग स्पष्ट चेतावनी चिह्न हों। न्यायालय ने 'टोटल शुगर' और 'सैचुरेटेड फैट' को प्रमुखता से दिखाने तथा 'हाई शुगर', 'हाई फैट और 'हाई साल्ट' जैसे स्पष्ट संकेत देने की दिशा में कदम उठाने को कहा है। उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है-उपभोक्ता को वह जानकारी सामने मिले, जिसे वह छोटे अक्षरों में खोजते-खोजते अक्सर छोड़ देता है।यह फैसला केवल लेबल बदलने का फैसला नहीं है, यह उस सोच को बदलने का प्रयास है जिसमें चमकदार पैकेट देखकर भोजन की गुणवत्ता तय कर ली जाती है। आज बाजार में किसी उत्पाद का विज्ञापन उसकी पौष्टिकता से अधिक आकर्षक पैकेजिंग, स्वाद और सुविधा बेचता है। बच्चे रंगीन पैकेट से आकर्षित होते हैं, युवा त्वरित भोजन को जीवनशैली समझने लगे हैं और व्यस्त परिवारों के लिए डिब्बाबंद भोजन समय बचाने का आसान विकल्प बन गया है। समस्या तब पैदा होती है जब सुविधा धीरे-धीरे आदत और आदत बीमारी में बदल जाती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि भोजन का अर्थ बदल रहा है। भोजन कभी जीवन को पोषण देने की प्रक्रिया था, अब वह तेजी से उपभोग की वस्तु बन रहा है। अधिक नमक, अधिक चीनी और अधिक वसा हमारे स्वाद की इंद्रियों को तो संतुष्ट कर सकते हैं, लेकिन शरीर की जरूरतों को नहीं। स्वाद की जीभ छोटी अवधि की खुशी चाहती है, जबकि शरीर दीर्घकालिक संतुलन मांगता है। बाजार ने हमारी जीभ को जीतने की कोशिश की है, अब हमें अपने विवेक को जीतना होगा।

भारत जैसे देश में यह चुनौती और गंभीर है, क्योंकि यहां भोजन केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, संस्कृति का हिस्सा है। हमारी परंपरा में 'जैसा अन्न वैसा मन' की धारणा रही है। भोजन को आयु, ऋतु, प्रकृति और श्रम के अनुरूप लेने की परंपरा थी। भारतीय रसोई में अनेक ऐसे खाद्य पदार्थ मौजूद हैं जिन्हें आज दुनिया 'सुपरफूड' कहकर खोज रही है। बाजरा, जौ, दालें, तिल, मूंगफली, विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां और स्थानीय खाद्य परंपराएं हमारी अपनी विरासत हैं। विडंबना यह है कि जिन खाद्य पदार्थों की ओर दुनिया स्वास्थ्य के लिए लौट रही है, हम उन्हीं को छोड़कर अत्यधिक प्रसंस्कृत और पैकेटबंद खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की पहल को केवल उपभोक्ता अधिकार का विषय मानना पर्याप्त नहीं होगा। इसे भारतीय खाद्य संस्कृति के पुनर्जागरण के अवसर के रूप में देखना चाहिए।

सरकार की जिम्मेदारी भी यहां बहुत बड़ी है। खाद्य सुरक्षा का अर्थ केवल यह सुनिश्चित करना नहीं होना चाहिए कि उत्पाद खाने योग्य है, यह भी देखना होगा कि उपभोक्ता को उस उत्पाद के वास्तविक स्वास्थ्य प्रभाव की जानकारी आसानी से मिले। एफएसएसएआई को वैज्ञानिक, स्पष्ट और उपभोक्ता-केंद्रित नियम बनाने होंगे। केवल नियम बनाना पर्याप्त नहीं, उनका प्रभावी निरीक्षण और कठोर पालन भी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश इसी दिशा में नियामकीय व्यवस्था को मजबूत करने का अवसर देता है। लेकिन सारी जिम्मेदारी सरकार या अदालत की नहीं हो सकती। उपभोक्ता को भी अपनी थाली का प्रहरी बनना होगा। जिस प्रकार हम घर खरीदते समय कीमत, स्थान और गुणवत्ता देखते हैं, उसी प्रकार भोजन खरीदते समय उसके घटकों को देखना भी हमारी आदत बननी चाहिए। किसी पैकेट पर बड़ा 'हेल्दी' लिखा होना उसे स्वतः स्वस्थ नहीं बना देता। विज्ञापन स्वास्थ्य का प्रमाणपत्र नहीं है। असली प्रमाण उसके पोषण संबंधी विवरण और हमारी आवश्यकता के बीच संतुलन है। बच्चों के मामले में विशेष सावधानी आवश्यक है। बच्चे विज्ञापन और पैकेजिंग से सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं। यदि स्कूल के आसपास और डिजिटल माध्यमों पर अत्यधिक चीनी, नमक और वसा वाले खाद्य पदार्थों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया जाता रहेगा, तो स्वस्थ भोजन उनके लिए 'उबाऊ' और अस्वास्थ्यकर भोजन 'मजेदार' बन जाएगा। इसलिए स्कूलों को केवल पाठ्यपुस्तकों में स्वास्थ्य शिक्षा देने के बजाय कैंटीन और परिसर के आसपास उपलब्ध भोजन के माध्यम से भी स्वस्थ आदतें विकसित करनी होंगी। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों के आसपास ऐसे खाद्य पदार्थों और उनके विज्ञापनों पर नियंत्रण की दिशा में भी जोर दिया है। हमें यहां एक और क्रांतिकारी विचार पर काम करना होगा-'फूड लिटरेसी' को जनशिक्षा का हिस्सा बनाना। जिस तरह बच्चों को वित्तीय साक्षरता और डिजिटल साक्षरता सिखाई जा रही है, उसी तरह उन्हें खाद्य साक्षरता भी सिखाई जानी चाहिए। बच्चे जानें कि शुगर क्या करती है, अधिक नमक क्यों नुकसान पहुंचाता है, संतृप्त वसा क्या है, पैकेट पर लिखे पोषण-लेबल को कैसे पढ़ना है और ताजा स्थानीय भोजन क्यों बेहतर विकल्प हो सकता है। एक जागरूक बच्चा केवल स्वयं स्वस्थ नहीं रहेगा, वह अपने परिवार की भोजन-आदत भी बदल सकता है। साथ ही भारतीय खाद्य संस्कृति को आधुनिक रूप देकर पुनर्जीवित करने की जरूरत है। स्वस्थ भोजन का अर्थ यह नहीं कि स्वाद छोड़ दिया जाए। भारत के पास स्वाद और स्वास्थ्य का अद्भुत संतुलन बनाने की हजारों वर्ष पुरानी क्षमता है। जरूरत है कि बाजरा, दाल, सब्जियों, पारंपरिक पेयों और स्थानीय व्यंजनों को आधुनिक प्रस्तुति, स्वच्छ पैकेजिंग और उचित मूल्य के साथ नई पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। हमें विदेशी खाद्य संस्कृति का विरोध नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध खाद्य संस्कृति को इतना आकर्षक बनाना है कि भारतीय युवा उसे गर्व से अपनाए। इस दिशा में एक नया सामाजिक अभियान चल सकता है-'मेरी थाली, मेरी जिम्मेदारी।' परिवार सप्ताह में कम-से-कम कुछ दिन पैकेटबंद भोजन से दूरी बनाए, स्कूल स्वस्थ भोजन दिवस मनाएं, कार्यालयों में पौष्टिक भोजन को बढ़ावा मिले, सार्वजनिक संस्थान स्थानीय और पारंपरिक खाद्य पदार्थों को प्रोत्साहित करें तथा मीडिया भोजन के विज्ञापन में केवल स्वाद नहीं, स्वास्थ्य की चेतना भी जगाए। खाद्य उद्योग को भी शत्रु मानने के बजाय जिम्मेदार भागीदार बनाया जाना चाहिए। मुनाफा कमाना उसका अधिकार है, लेकिन उपभोक्ता के स्वास्थ्य की कीमत पर मुनाफा कमाना सामाजिक रूप से स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मूलतः एक सवाल हमारे सामने रखा है-क्या हमारी सुविधा हमारी सेहत से बड़ी हो गई है? इसका उत्तर हमें सामूहिक रूप से देना होगा। अदालत ने पैकेट के सामने चेतावनी लगाने का रास्ता दिखाया है, लेकिन असली चेतावनी हमारे विवेक पर लिखी जानी चाहिए। यदि लाल निशान देखकर भी हम वही चीज खरीदते रहें, तो केवल लेबल बदलने से समाज नहीं बदलेगा।

एक नजर

28 नवंबर से अंतर-क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता में 40 कॉलेजों के 200 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा



जगदलपुर, 28 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। बस्तर जिला मुख्यालय के कुम्हरावण्ड स्थित शहीद गुण्डाधूर कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र में आगामी 28 से 30 नवंबर तक खेलों का रोमांच देखने को मिलेगा। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता छात्र कल्याण के तत्वावधान में आयोजित इस तीन दिवसीय विश्वविद्यालय स्तरीय अंतर-क्षेत्रीय खेलकूद प्रतियोगिता की तैयारियां जोर-शोर से अंतिम चरण में हैं। इस खेल महाकुंभ में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से 5 अंतर-क्षेत्रीय टीमों के करीब 200 छात्र-छात्राएं अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। प्रतियोगिता का विधिवत शुभारंभ 28 नवंबर 2026 (शनिवार) को प्रातः 11:00 बजे महाविद्यालय परिसर में होगा। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय, जगदलपुर के कुलपति प्रो. मनोज कुमार श्रीवास्तव होंगे। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अधिष्ठाता छात्र कल्याण डॉ. संजय शर्मा शिरकत करेंगे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मेजबान महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉ. आर.एस. नेताम करेंगे। उद्घाटन अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में विभिन्न कृषि महाविद्यालयों के अधिष्ठाता एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इनमें डॉ. संतोष कुमार सिन्हा (अंबिकापुर), डॉ. एस.एल. स्वामी (बिलासपुर), डॉ. एच.एल. सोनबोइर (भाठापारा), डॉ. ललित रामटेके (साजा, बेमेतरा) और परिक्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र जगदलपुर के सह संचालक अनुसंधान डॉ. ए.के. ठाकुर शामिल हैं। आयोजन सचिव एवं क्रीड़ा प्रभारी डॉ. आरआर कंवर ने बताया कि प्रतियोगिता में कुल 17 खेल विधाओं को शामिल किया गया है। इनमें एथलेटिक्स के अंतर्गत 100, 200, 400, 800 व 1500 मीटर दौड़, हाई जंप और लॉन्ग जंप के मुकाबले होंगे। इसके अलावा कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस और बैडमिंटन (सिंगल व डबल) में भी खिलाड़ी जोर आजमाइश करेंगे। मैचों के निष्पक्ष और पारदर्शी संचालन के लिए शासकीय विद्यालयों के 10 अनुभवी रेफरियों की नियुक्ति की गई है। इस प्रतियोगिता में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के दक्षिण, उत्तर, पूर्वी, पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्रों के 29 शासकीय और 11 निजी कुल 40 महाविद्यालयों के चयनित खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। टीमों के जगदलपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। महाविद्यालय प्रबंधन ने खेल मैदानों को संवारने के साथ-साथ बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के आवास, भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई है।

बादल में अनियमित पद के लिए चल-साक्षात्कार 21 दिसम्बर को

जगदलपुर, 28 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। आमचो बस्तर हेरिटेज सोसायटी बादल आसना के अंतर्गत संचालित संस्था 'बस्तर एकेडमी ऑफ डांस, आर्ट एण्ड लिटरेचर (बादल)', आसना, जगदलपुर में 01 अनियमित पद (अनारक्षित) पर सेवा लेने के लिए चल-साक्षात्कार (वॉक इन इंटरव्यू) आयोजित किया जा रहा है। साक्षात्कार का आयोजन सोमवार 21 दिसंबर 2026 को प्रातः 10:30 बजे से कार्यालय आमचो बस्तर हेरिटेज सोसायटी बादल आसना, जगदलपुर, जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़) में किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी पद से जुड़ी विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का निर्धारित प्रारूप बस्तर जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://bastar.gov.in पर देख और डाउनलोड कर सकते हैं।

'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' के ऐतिहासिक 100वें संस्करण का आयोजन 29 नवंबर को

- कलेक्टर कार्यालय से कारली चौक तक आयोजित होगी रैली, युवाओं और नागरिकों को दिया जाएगा फिटनेस एवं स्वस्थ जीवनशैली का संदेश

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



दंतेवाड़ा 28 नवंबर। जिले में फिटनेस और स्वस्थ जीवनशैली के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से रविवार, 29 नवंबर 2026 को 'फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल' अभियान के ऐतिहासिक 100वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार की पहल पर मेरा युवा भारत (माय भारत), दंतेवाड़ा द्वारा इस अवसर पर विशेष साइकिल रैली निकाली जाएगी।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार साइकिल रैली कलेक्टर कार्यालय, दंतेवाड़ा से प्रारंभ होकर कारली चौक तक पहुंचेगी। इसके पश्चात रैली पुनः कलेक्टर कार्यालय लौटेगी। आयोजन के माध्यम से जिले के युवाओं, युवा मंडलों, खेल प्रेमियों एवं आम नागरिकों को नियमित व्यायाम, शारीरिक फिटनेस, खेल भावना और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा।

अभियान का 100वां संस्करण भारत के ओलंपिक आंदोलन और भविष्य में ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के देश के संकल्प को समर्पित है। इस विशेष आयोजन की थीम ओलंपिक के तीन मूलभूत मूल्यों उत्कृष्टता, सम्मान और मित्रता पर आधारित है। साइकिल रैली के जरिए युवाओं में अनुशासन, आपसी सहयोग, खेल भावना और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2024 में शुरू हुआ 'संडे ऑन साइकिल' अभियान देशभर में फिटनेस जागरूकता का एक महत्वपूर्ण माध्यम बन चुका है। अभियान का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री के संदेश 'फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज' को जन-जन तक पहुंचाना है। साइकिलिंग न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, बल्कि यह पर्यावरण अनुकूल परिवहन और सक्रिय जीवनशैली को भी प्रोत्साहित करती है।

मेरा युवा भारत, दंतेवाड़ा द्वारा जिले के समस्त युवाओं एवं नागरिकों से इस ऐतिहासिक आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है, ताकि फिटनेस को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर स्वस्थ, सक्रिय एवं खेलप्रेमी भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।

एनएमडीसी ने दावा किया, डिपॉजिट-14 भूस्खलन खनन क्षेत्र से बाहर हुई भूगर्भीय हलचल के कारण

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



दंतेवाड़ा, 28 नवंबर। जिले में बैलाडीला के किरंदुल स्थित एनएमडीसी के डिपॉजिट-14 में हुए भूस्खलन को लेकर कंपनी ने अपनी प्रारंभिक जांच और आकलन के आधार पर घटना की वजह बताई है। एनएमडीसी का दावा है कि खनन पट्टा क्षेत्र से लगभग दो किलोमीटर दूर जंगल में हुई प्राकृतिक भूगर्भीय हलचल के कारण यह स्थिति बनी। कंपनी के अनुसार इस हलचल का असर बाद में खदान के पुराने वेस्ट डंप पर पड़ा और उसका एक हिस्सा ढह गया, जिससे मलबा ढलान की ओर फैल गया।

घटना की वास्तविक वजह और जमीन के भीतर की स्थिति समझने के लिए आईआईटी बॉम्बे के विशेषज्ञों की मदद से वैज्ञानिक अध्ययन कराया जा रहा है। दूसरी ओर, वन विभाग ने शुरुआती आकलन में करीब 30 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र के प्रभावित होने की बात कही है। विभाग ने संबंधित एजेंसी के खिलाफ वन अपराध भी दर्ज किया है।

कंपनी के अनुसार 18 नवंबर को बैलाडीला की पहाड़ियों के पीछे स्थित वन क्षेत्र में भूगर्भीय हलचल हुई थी। इसका असर सबसे पहले लोहागांव की ओर बन रही ग्रामीण सड़क और आसपास के इलाके में दिखाई दिया। एनएमडीसी का कहना है कि इसी प्राकृतिक घटना का प्रभाव खनन पट्टे के भीतर मौजूद पुराने वेस्ट डंप तक पहुंचा, जिसके एक हिस्से में ढहाव हुआ। कंपनी ने इस घटना को खनन गतिविधियों से सीधे शुरू हुई घटना के बजाय बाहरी भूगर्भीय हलचल का प्रभाव बताया है। हालांकि, इसकी पुष्टि वैज्ञानिक जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी। वन विभाग के शुरुआती निरीक्षण में करीब 30 हेक्टेयर आरक्षित वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। विभाग के अनुसार कंपार्टमेंट क्रमांक 673 में पेड़-पौधों और प्राकृतिक वनस्पति पर असर पड़ा है। इसके अलावा लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर लंबा नाला भी मलबे की चपेट में आया है। एनएमडीसी के अनुसार, कंपनी, वन विभाग और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने मौके का निरीक्षण किया था। इसमें वेस्ट डंप से निकली खनन अपशिष्ट सामग्री के ढलान के निचले हिस्से तक करीब 200 से 250 मीटर पहुंचने की बात सामने आई। वहीं, पहाड़ी की प्राकृतिक मिट्टी और बजरी लगभग 2 से 3 किलोमीटर तक बहकर पहुंची। कंपनी ने शुरुआती आकलन में भूमिगत जलधारा की संभावित भूमिका से भी इनकार नहीं किया है।

एनएमडीसी ने अपने पुराने तकनीकी रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा है कि संबंधित वेस्ट डंप करीब दो दशक पुराना है और इसकी स्थिरता के लिए समय-समय पर इंजीनियरिंग उपाय किए गए थे। इनमें ढलान को मजबूत रखने के लिए सीढ़ीनुमा संरचनाएं, बारिश के पानी की निकासी के लिए गारलैंड ड्रेन, आधार को सहारा देने के लिए टो बट्रेस वॉल और स्थानीय प्रजातियों के पौधों का रोपण शामिल था। कंपनी के मुताबिक, धनबाद स्थित केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान (ष्टढ्ढरूस्त्रक्र) ने भी इस डंप की स्थिरता का अध्ययन किया था। जनवरी 2026 में मिली रिपोर्ट में इसे सुरक्षित बताया गया था। इसके साथ ही नियमित मासिक सर्वेक्षणों में भी सतह पर किसी बड़ी हलचल का संकेत नहीं मिला था।

भूस्खलन के कारणों और प्रभावित क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का पता लगाने के लिए अब विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययन किया जा रहा है। इसके तहत ड्रोन से सर्वे कर प्रभावित हिस्से की ऑर्थोमोजेक तस्वीरें तैयार की जाएंगी। इनकी मदद से मलबे के फैलाव

बचेली एवं किरंदुल में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग ने शांति के लिए निकाला संयुक्त फ्लैग मार्च

- एनएमडीसी की एल-1 एवं एल-2 भर्ती प्रक्रिया को लेकर बनी स्थिति के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

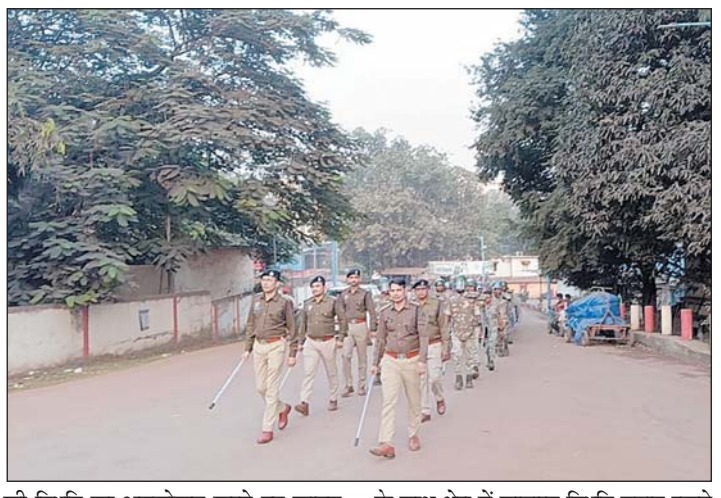

दंतेवाड़ा 28 नवंबर। एनएमडीसी की बचेली एवं किरंदुल परियोजनाओं में एल-1 एवं एल-2 भर्ती प्रक्रिया को लेकर उत्पन्न स्थिति के मद्देनजर जिले में शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस विभाग द्वारा दोनों नगरों में संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला गया।

फ्लैग मार्च के दौरान जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों ने बचेली और किरंदुल के विभिन्न क्षेत्रों में पैदल मार्च कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान आम नागरिकों को शांति, सौहार्द और आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया गया। अधिकारियों ने क्षेत्र की स्थिति का अवलोकन करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन की सतर्कता और तैयारियों का भी जायजा लिया। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों से अपील की गई कि वे क्षेत्र में शांति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों से दूर रहें। प्रशासन ने नागरिकों से आपसी सहयोग एवं जिम्मेदारी के साथ क्षेत्र में सामान्य स्थिति बनाए रखने की अपील की।

इस संयुक्त फ्लैग मार्च में पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जितेंद्र खुटे, एसडीएम राजीव कुजूर, एसडीएम मनीष बघेल, डिप्टी कलेक्टर अमित भारद्वाज एवं डिप्टी कलेक्टर चंचल पैकरा सहित जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

शैक्षणिक भ्रमण में विद्यार्थियों को दी गई वाहनों की तकनीक जानकारी

जगदलपुर, 28 नवंबर। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय करीतगांव में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए शुक्रवार को एक दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत करीतगांव एवं गुमडेल में आयोजित इस भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों को ऑटोमोबाइल वाहनों की तकनीक, विभिन्न पुर्जों और उनकी कार्यप्रणाली की व्यावहारिक जानकारी दी गई। संस्था की प्राचार्य मोनिता पाणिग्राही ने विद्यार्थियों को भ्रमण के लिए रवाना किया। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से प्राप्त तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल विद्यार्थियों को भविष्य में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के साथ आत्मनिर्भर बनने में भी सहायक होंगे। भ्रमण के दौरान ऑटो सेंटर के प्रशिक्षक गुप्ते पाणिग्राही ने विद्यार्थियों को मोटरसाइकिल के इंजन, बैटरी, ब्रेक, क्लच, एक्सीलेटर सहित विभिन्न महत्वपूर्ण पुर्जों की जानकारी दी।

यूपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण एससी-एसटी अभ्यर्थियों को मिलेगी एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

दंतेवाड़ा 28 नवंबर। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा परीक्षा में अपना भविष्य बनाने का सपना देख रहे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर है। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले इन वर्गों के पात्र अभ्यर्थियों को शासन की प्रोत्साहन योजना के तहत एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य प्रतिभाशाली युवाओं को सिविल सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना तथा मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराना है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हेतु प्रोत्साहन योजना (यथा संशोधित) वर्ष 2010 के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के तहत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को निर्धारित पात्रता एवं नियमों के अनुसार एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।

विभाग द्वारा आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन तैयार कर अंतिम तिथि तक संबंधित कार्यालय में जमा करना होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन प्रस्तुत करने से पहले योजना की पात्रता, नियम एवं शर्तों का अच्छी तरह अध्ययन कर लें, ताकि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी न हो।

योजना से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता की शर्तें, आवश्यक नियम एवं आवेदन पत्र का निर्धारित प्रारूप आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://eklavya.cg.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदन पत्र भरकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र कार्यालय आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, ब्लॉक-डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (छत्तीसगढ़) के पते पर जमा करना होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन जमा करने के पश्चात संबंधित शाखा से पावती प्राप्त करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी अपना आवेदन निर्धारित पते पर रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भी भेज सकते हैं। आवेदन भेजते समय यह सुनिश्चित करना होगा कि वह निर्धारित समय-सीमा के भीतर संबंधित कार्यालय तक पहुंच जाए।

सिविल सेवा परीक्षा देश की प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल है। इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए अभ्यर्थियों को लंबे समय तक अध्ययन, नियमित अभ्यास और बेहतर मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए भी पर्याप्त समय और संसाधनों की जरूरत होती है। ऐसे में शासन की ओर से दी जाने वाली एक लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि पात्र अभ्यर्थियों के लिए आर्थिक रूप से सहायक हो सकती है।

विभाग की इस पहल से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के युवाओं को सिविल सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में आने वाली कठिनाइयों को कम करने में भी मदद मिल सकती है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने जिले सहित प्रदेश के सभी पात्र अभ्यर्थियों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए समय पर आवेदन प्रस्तुत करें। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 17 दिसंबर 2026 है, इसलिए अभ्यर्थी अंतिम समय की प्रतीक्षा न करते हुए जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया पूरी करें और सिविल सेवा परीक्षा में अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाएं।

जिला स्तरीय निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सम्मानित

- जिले के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक लिया हिस्सा, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र देकर किया गया सम्मानित

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता



दंतेवाड़ा 28 नवंबर। विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक मूल्यों, मताधिकार के महत्व और निर्वाचन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में निर्वाचन साक्षरता क्लब (ईएलसी) के अंतर्गत जिला स्तरीय निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़, रायपुर के निर्देशानुसार संयुक्त जिला कार्यालय दंतेवाड़ा के सभाकक्ष में आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न महाविद्यालयों, प्रशिक्षण संस्थानों एवं हायर सेकेंडरी विद्यालयों से चयनित छात्र-छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

प्रतियोगिता का आयोजन दोपहर 12:30 बजे किया गया। इसमें विद्यार्थियों को निर्वाचन प्रक्रिया, लोकतांत्रिक व्यवस्था, नागरिक अधिकारों तथा मतदाता के कर्तव्यों से संबंधित विषयों पर अपनी जानकारी और समझ प्रदर्शित करने का अवसर मिला। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता के माध्यम से विद्यार्थियों की सामान्य जानकारी एवं तार्किक क्षमता का आकलन किया गया, वहीं निबंध प्रतियोगिता में उनके लेखन कौशल, विचारों की स्पष्टता और लोकतांत्रिक विषयों की समझ को परखा गया।

प्रतियोगिता में शामिल छात्र-छात्राओं ने पूरे उत्साह के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्राप्त प्रविष्टियों एवं उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के बाद उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में इन विद्यार्थियों ने किया उत्कृष्ट प्रदर्शन

प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रशिक्षण संस्थान दंतेवाड़ा की कु. इंदू नेताम एवं कु. पूजा नेताम, कन्या शिक्षा परिसर पातररास की कु. पायल नाग, प्रशिक्षण संस्थान भांसी के श्री संदीप सोना, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय किरंदुल की कु. निलांजना नाग, आस्था विद्या मंदिर जावंगा के श्री लयश ठाकुर एवं श्री हर्षवर्धन ठाकुर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

इसी क्रम में सेजस समलूर के श्री सुजल सरकार, सेजस कारली जावंगा की कु. महिमा कश्यप, हाईस्कूल आंवराभाटा के श्री दोसल राम पोयाम तथा सेजस कारली के श्री दिनेश कुमार कुंजाम सहित अन्य प्रतिभागियों ने भी सराहनीय प्रदर्शन किया।

निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने दिखाई लेखन प्रतिभा

निबंध प्रतियोगिता में प्रशिक्षण संस्थान भांसी के श्री किशोर कुमार साहू, सेजस आकाश नगर कासोली गीदम के श्री मनोज कुमार यादव, प्रशिक्षण संस्थान कारली दंतेवाड़ा की कु. हिमांशी साहू, प्रशिक्षण संस्थान कारली गीदम के श्री कामेश्वर उद्दे तथा सेजस पोन्दुम की कु. ईशा पंत ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

इसके अलावा सेजस कन्या शाला विद्यानगर किरंदुल की कु. कावेरी, कन्या शिक्षा परिसर पातररास की कु. निधि कश्यप एवं कु. महेश्वरी ठाकुर, सेजस गीदम की कु. मोहनी बघेल, कन्या शिक्षा परिसर जावंगा की कु. जान्हवी मंडावी, कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दंतेवाड़ा के श्री देवेंद्र यादव तथा सेजस समलूर के अन्य प्रतिभागियों ने भी अपनी प्रतिभा का सराहनीय प्रदर्शन किया।

जिम्मेदार नागरिक एवं जागरूक मतदाता बनाने पर जोर

कार्यक्रम के दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी दंतेवाड़ा ने जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स, निर्वाचन साक्षरता क्लब के नोडल अधिकारियों एवं प्रतियोगिता में शामिल सभी छात्र-छात्राओं का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सभी के सहयोग और उत्साहपूर्ण सहभागिता की सराहना की। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों एवं युवाओं को लोकतांत्रिक व्यवस्था की बुनियादी जानकारी देना, निर्वाचन प्रक्रिया से परिचित कराना तथा मतदान के अधिकार और उसके महत्व को समझाना है। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों में लोकतांत्रिक चेतना विकसित करने के साथ उन्हें अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक बनाया जा रहा है। निर्वाचन साक्षरता क्लब के माध्यम से युवाओं को यह संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि लोकतंत्र की मजबूती में प्रत्येक नागरिक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जागरूक मतदाता ही निष्पक्ष, स्वतंत्र एवं मजबूत लोकतांत्रिक व्यवस्था की आधारशिला है। ऐसे आयोजन विद्यार्थियों को भविष्य में जिम्मेदार मतदाता बनने के लिए प्रेरित करने के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी समझ को भी मजबूत करते हैं।

धान खरीदने की भाजपा सरकार की मंशा ही नहीं, 15 जनवरी तक टोकन फुल तो क्या खरीदी बंद होने के बाद धान बेचेगा किसान: चंदन कश्यप

जगदलपुर, 28 नवंबर। पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने धान खरीदी में मचे हाहाकार को लेकर भाजपा सरकार पर करारा प्रहार किया है। उन्होंने स्पष्ट आरोप लगाया कि भाजपा सरकार की धान खरीदने की मंशा ही नहीं है और वह सुनियोजित तरीके से प्रदेश के अन्नदाताओं को उनकी मेहनत की कमाई से वंचित करने का षड्यंत्र रच रही है। ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की पोल खोलते हुए श्री कश्यप ने तीखा सवाल दागा, सरकार की नीयत में खोट इसी बात से साफ है कि धान खरीदी के लिए मात्र 45 दिन का समय रखा गया है, और विडंबना देखिए कि ऑनलाइन पोर्टल में 15 जनवरी तक के सारे टोकन अभी से फुल दिखा रहे हैं। जब किसानों को अभी से टोकन नहीं मिल रहा है, तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या किसान धान खरीदी बंद होने के बाद अपनी फसल बेचेगा?÷ खरीदी केंद्रों में टोकन की बेहद कम सीमा पर आक्रोश जताते हुए पूर्व विधायक ने कहा, ÷समितियों में प्रतिदिन केवल 200 से 300 क्विंटल का ही टोकन काटा जा रहा है, जबकि किसानों की भारी संख्या को देखते हुए प्रतिदिन कम से कम 2000 क्विंटल का टोकन कटना चाहिए। 200 से 300 क्विंटल धान तो एक ही बड़े किसान का होता है। ऐसे में क्षेत्र के बाकी छोटे और मध्यम किसानों का नंबर आखिर कब आएगा? उन्होंने कहा कि एक तरफ सरकार बड़े-बड़े विज्ञापन छपवाकर किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है, तो दूसरी तरफ जमीनी हकीकत यह है कि किसान टोकन के लिए रोज समितियों और चॉइस सेंटरों के चक्कर काटकर परेशान हो रहे हैं। सरकार की इस किसान विरोधी नीति के कारण अन्नदाता मजबूरी में बिचौलियों और कोचियों के हाथों औने-पौने दामों पर धान बेचने के लिए विवश हो रहे हैं। पूर्व विधायक चंदन कश्यप ने सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मांग की है कि: प्रतिदिन की टोकन सीमा तत्काल बढ़ाकर 2000 क्विंटल की जाए। ऑनलाइन पोर्टल में आ रही टोकन की समस्या को तुरंत दूर कर सभी किसानों को समय पर टोकन उपलब्ध कराया जाए।

602 किसानों से समर्थन मूल्य पर 3,254 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीदी

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

किसान दिनेश पटेल ने धान खरीदी व्यवस्था पर जताया संतोष, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति व्यक्त किया आभार

रायगढ़, 28 नवम्बर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मंशानुरूप एवं शासन के निर्देशानुसार खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य निरंतर जारी है। जिले के 112 उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए धान खरीदी की व्यवस्था की गई है। अब तक जिले में 602 किसानों से कुल 3,254.08 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। उपार्जन केंद्रों में किसानों को धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए पेयजल, छाया सहित आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही धान की तौल के लिए बायोमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक तराजू का उपयोग किया जा रहा है, जिससे तौल प्रक्रिया में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित हो रही है।



घर बैठे टोकन लेने की भी सुविधा

धान खरीदी प्रक्रिया को किसानों के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से ऑनलाइन और समिति स्तर पर टोकन प्राप्त करने के दोनों विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। 'तुंहर टोकन' मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान घर बैठे अपने मोबाइल से टोकन प्राप्त कर सकते हैं। वहीं, ऐप के माध्यम से टोकन लेने में असुविधा होने पर संबंधित सहकारी समिति से भी टोकन प्राप्त करने की सुविधा है।

21 क्विंटल प्रति एकड़ की पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं

कृषक उन्नति योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति एकड़ 13 हजार 839 रुपये की दर से आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल धान की पूरी मात्रा बेचना अनिवार्य नहीं है। निर्धारित मात्रा से कम धान विक्रय करने वाले पात्र किसान भी योजना के प्रावधानों के अनुसार आदान सहायता के पात्र होंगे।

धानगर मंडी में धान विक्रय करने पहुंचे ग्राम बघनपुर के किसान दिनेश पटेल ने मंडी की व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। उन्होंने बताया कि उन्होंने धान विक्रय के लिए टोकन कटवाया था। उनका 11 क्विंटल 7 किलोग्राम धान धनागर मंडी में तौल किया गया। उन्होंने कहा कि मंडी में किसानों के लिए छाया और पानी की अच्छी व्यवस्था है। बायोमेट्रिक इलेक्ट्रॉनिक तराजू से धान की तौल होने से किसानों को सुविधा मिल रही है।

उन्होंने कहा कि मंडी में सभी व्यवस्थाएं ठीक हैं और धान खरीदी की प्रक्रिया भी अच्छी तरह संचालित हो रही है। इसके लिए उन्होंने शासन-प्रशासन का आभार जताते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति किसान की ओर से धन्यवाद व्यक्त किया।

समाचार संक्षेप

खेत में गिरने के बाद हाथी का शावक उठ नहीं पाया,इलाज किया जा रहा



■ वन अमला व डाक्टर जूटे इलाज में, हालात में नहीं हो रहा सुधार

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 28 नवम्बर। रायगढ़ जिले का धरमजयगढ़ वन मंडल एक बार फिर हाथियों की सुरक्षा और संरक्षण को लेकर सवालों के घेरे में है। आलम यह है कि यह इलाका अब बेबी एलिफेंट का कब्रगाह बनता जा रहा है। क्षेत्र में अब तक चार से पांच हाथी शावकों की मौत के बाद, आज 27 नवंबर को सुबह एक और दर्दनाक तस्वीर सामने आई, जहाँ लगभग 6 साल का एक हाथी शावक खेत में गिरने के बाद खुद से उठ नहीं पायय

यह 6 साल का हाथी शावक अपने दल से अलग होकर अकेले विचरण करते हुए रात में ब आईनहर गांव के करीब पहुंच गया था। इस दौरान उसने वहां खड़ी एक कार को मामूली रूप से क्षति भी पहुंचाई थी उस के बाद वह सुबह गांव के ही एक खेत में गिरा हुआ मिला । शावक की हालत इतनी नाजुक थी कि वह काफी देर तक कोशिश करने के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका।

सुबह ग्रामीणों और हाथी ट्रैकरों से सूचना मिलते ही धरमजयगढ़ के एसडीओ, रेंजर और वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। शावक की गंभीर हालत को देखते हुए खेत में ही उसका रेस्क्यू और इलाज शुरू किया गया। स्थानीय पशु चिकित्सकों की टीम लगातार उसका इलाज कर रही है, वहीं बेहतर उपचार के लिए बाहर से विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। लेकिन अभी तक किसी सुधार की कोई खबर नहीं है। वन विभाग का अमला मौके पर डटा हुआ है और शावक की हर हरकत पर पैनी नजर रखी जा रही है। लगातार हो रही हाथी शावकों की मौतों के बीच अब इस नन्हे हाथी की जान बचाना वन विभाग के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है।

एक नजर

फिट इंडिया अभियान के तहत 29 नवंबर को रायगढ़ में निकलेगी साइकिल रैली

रायगढ़, 28 नवम्बर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। फिट इंडिया मूवमेंट के तहत नागरिकों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के उद्देश्य से 29 नवंबर रविवार को रायगढ़ में 'संडे ऑन साइकिल' रैली का आयोजन किया जाएगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित यह रैली सुबह 8 बजे रायगढ़ स्टेडियम बोईरदादर से प्रारंभ होगी। रैली रायगढ़ स्टेडियम बोईरदादर से शुरू होकर चक्रधर चौक, सिग्नल चौक तक जाएगी और वापस चक्रधर चौक होते हुए रायगढ़ स्टेडियम में संपन्न होगी। इस आयोजन में स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, एनसीसी, एनएसएस, माय भारत के स्वयंसेवक तथा गणमान्य नागरिकों सहित लगभग 300 से 350 प्रतिभागियों के शामिल होंगे। यह आयोजन 'संडे ऑन साइकिल' अभियान के 100वें संस्करण के अवसर पर देशभर में आयोजित किया जाएगा।

रेत के अवैध उत्खनन पर खनिज विभाग 21 वाहन जब्त किए



रायगढ़, 28 नवम्बर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिले में खनिज रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के विरुद्ध खनिज विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खनिज उड़नदस्ता दल ने लेबडा-देवरी-रानीगुड़ा क्षेत्र में सुबह 6 बजे दबिश देकर अवैध उत्खनन एवं परिवहन में संलिप्त कुल 21 वाहनों पर कार्रवाई की। जिसमें 1 चैन माउंटेन मशीन, 4 जेसीबी मशीन, 1 ट्रैक्टर लोडर और 15 ट्रैक्टर शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान चैन माउंटेन मशीन को मौके पर ही सील किया गया। वहीं 5 ट्रैक्टरों को पुलिस थाना खरसिया की अभिरक्षा में रखा गया है। इसके अलावा 4 जेसीबी मशीन, 1 ट्रैक्टर लोडर और 10 ट्रैक्टरों को जिला कार्यालय परिसर में रखा गया है। जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि विभाग द्वारा जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। वहीं इस कार्य में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में खनि निरीक्षक सोमेश्वर सिन्हा एवं अनुराग बड़ा सहित खनिज उड़नदस्ता दल के सिपाही शामिल रहे।

कुष्ठ रोग की समय पर पहचान और उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

रायगढ़, 28 नवम्बर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत जिले के सभी विकासखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों को 26 एवं 27 नवंबर को दो दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिसमें कुष्ठ रोग के लक्षणों और उपचार की जानकारी दी गई। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल कुमार जगत ने नर्व स्थिति की पहचान और दिव्यांगता से बचाव के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों को छिपे हुए कुष्ठ रोगियों की पहचान कर उन्हें नियमानुसार एमडीटी दवा का पूरा उपचार दिलाने के निर्देश दिए। जिला कुष्ठ अधिकारी डॉ. अविनाश चंद्रा ने प्रशिक्षण में बताया कि त्वचा पर हल्के रंग के दाग-धब्बे, प्रभावित हिस्से में स्पर्श का एहसास कम होना या समाप्त होना, नसों में सूजन अथवा मोटापन और कान में गांठ जैसे लक्षण कुष्ठ रोग के संकेत हो सकते हैं।

धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 28 नवम्बर। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देशानुसार जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान धान के अवैध भंडारण और परिवहन पर रोक लगाने के लिए प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा दो अलग-अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से भंडारित एवं परिवहन किए जा रहे धान को जब्त किया।

26 नवंबर को रायगढ़ तहसील के ग्राम कोयलंगा में मंडी एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने आयुष किराना स्टोर की जांच की। इस दौरान दुकान में अवैध रूप से भंडारित 26 कट्टा धान, जिसकी मात्रा



11 क्विंटल थी, को मंडी अधिनियम के तहत जब्त किया गया। साथ ही 27 नवंबर को अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशन में खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने लैलूंगा में कार्रवाई की। टीम ने शंकर यादव निवासी सुरंगपानी द्वारा पिकअप वाहन क्रमांक में टीएसएस लैलूंगा में विक्रय के लिए लाए गए 70 बोरी धान को जब्त किया। विकासखंड धरमजयगढ़ कापू में खाद्य एवं राजस्व विभाग के संयुक्त दल द्वारा गुप्ता किराना के गोदाम से 180 क्विंटल अवैध धान जपती की कार्रवाई की गई। जिले में धान के अवैध भंडारण, परिवहन और अनियमित खरीदी-बिक्री पर निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन द्वारा ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए जांच एवं कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

जिले में पीएम आवास के 5,300 घरों में मुफ्त लगेंगे सोलर संयंत्र

रायगढ़, 28 नवम्बर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। शासन के निर्देशानुसार प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से जिले में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष पहल की जा रही है। इसके तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग जिले के 5,300 चिन्हित आवासों में यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल के अंतर्गत निःशुल्क सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं यूएलए मॉडल के दायरे से बाहर रहने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को भी योजना से जोड़ने के लिए कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

■ अन्य घरेलू उपभोक्ताओं को भी सोलर संयंत्र लगाने पर मिलेगी सब्सिडी

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिजीत बबन पठारे की अध्यक्षता में जिला पंचायत के सभाकक्ष में स्थानीय सोलर वेंडरों, बैंक अधिकारियों एवं सीएसपीडीसीएल के अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। इसमें पात्र उपभोक्ताओं को योजना से जोड़ने, बैंकिंग प्रक्रिया को सरल बनाने तथा सोलर संयंत्रों की स्थापना में तेजी लाने पर चर्चा हुई। बैठक में स्थानीय वेंडरों को अधिकाधिक घरेलू उपभोक्ताओं तक पहुंचकर योजना का लाभ दिलाने और निर्धारित समय-सीमा में स्थापना कार्य पूरा करने के लिए लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में बताया गया कि यूएलए मॉडल से अलग अन्य पात्र घरेलू उपभोक्ता भी स्थानीय वेंडरों के माध्यम से 2 किलोवाट तक का सोलर रूफटॉप संयंत्र लगवा सकेंगे। ऐसे संयंत्र की अनुमानित स्थापना लागत लगभग 90 हजार रुपये है। पात्र हितग्राहियों को केंद्र एवं राज्य शासन के निर्धारित प्रावधानों के अनुसार अनुदान मिलेगा,जिसकी कुल राशि 2ङ्ग सिस्टम के लिए 90 हजार रुपए है। इस प्रकार दोनों शासन की सब्सिडी का लाभ मिलने के बाद संयंत्र की लागत हितग्राही के लिए प्रभावी रूप से शून्य हो जाएगी। इस पहल से घरेलू उपभोक्ताओं को अपने घरों में सौर ऊर्जा अपनाने का अवसर मिलेगा। साथ ही बिजली बिल में बचत होने के साथ स्वच्छ एवं पर्यावरण अनुकूल ऊर्जा के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।

सी.एम. हेल्पलाइन से ग्रामीणों की पेयजल समस्या का समाधान हुआ

1076 में शिकायत पर शीघ्र कार्यवाही, सुधार के बाद सोलर ड्यूल पंप हुआ चालू

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 28 नवम्बर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर आम नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता के साथ दूर करने की दिशा में शासन-प्रशासन लगातार काम कर रहा है। सी.एम. हेल्पलाइन 1076 इस व्यवस्था में आम लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है। इसका उदाहरण धरमजयगढ़ विकासखंड के ग्राम भालूपखना, घुटरापारा में देखने को मिला, जहां शिकायत मिलते ही खराब सोलर ड्यूल पंप को दुरुस्त कर पेयजल व्यवस्था बहाल की गई।

ग्राम निवासी नंद कुमार ने जल जीवन मिशन के तहत स्थापित सोलर ड्यूल पंप के बंद होने की शिकायत सी.एम. हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई थी। पंप में खराबी के कारण ग्रामीणों को पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ रही थी। शिकायत पर क्रेडा विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए मैकेनिक से पंप का जांच कराया गया। जिसमें तकनीकी खराबी सामने आने पर आवश्यक सुधार कार्य कर पंप को पुनः चालू कर दिया गया। अब पंप सुचारू रूप से काम कर रहा है और ग्रामीणों के



साथ राहगीरों को भी पेयजल की सुविधा मिल रही है। समस्या का समाधान होने पर शिकायतकर्ता नंद कुमार ने संतुष्टि जताई। वहीं ग्रामवासियों ने त्वरित कार्यवाही के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के प्रति आभार व्यक्त किया।

क्या है सी.एम. हेल्पलाइन 1076

सी.एम. हेल्पलाइन 1076 आम नागरिकों को अपनी समस्याएं सीधे शासन-प्रशासन तक पहुंचाने का माध्यम है। इस पर दर्ज शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी जाती हैं, जहां अधिकारी शिकायत की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करते हैं। शिकायत के निराकरण के बाद आवेदक से उसकी संतुष्टि भी जानी जाती है। इसका उद्देश्य लोगों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत दिलाना और उनकी समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना है।

अनुसूचित जाति उप योजना के तहत 24 किसानों को मिला धनिया का आधार बीज



■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 28 नवम्बर। कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र, बोईरदादर रायगढ़ द्वारा किसानों को मसाला फसलों की खेती से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने के उद्देश्य से धनिया के आधार बीज का वितरण किया गया। अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति उप योजना के तहत ग्राम बड़े अमकोनी, विकासखंड बरमकेला में आयोजित कार्यक्रम में 24 किसानों को प्रति किसान 5 किलोग्राम की दर से धनिया का आधार बीज प्रदान किया गया। कार्यक्रम में कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र के अधिष्ठाता एवं परियोजना के प्रमुख अन्वेषक डॉ. ए.के. सिंह ने किसानों को धनिया की उन्नत खेती, फसल उत्पादन की तकनीक और बेहतर पैदावार के लिए आवश्यक सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने किसानों को वैज्ञानिक पद्धति अपनाकर खेती करने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर ग्रामीण उद्यान अधीक्षक हीरालाल देवांगन, ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी विनय कुमार पटेल एवं ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मनोज कुमार ने किसानों को मसाला फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने बताया कि मसाला फसलों की खेती अपनाकर किसान अपनी आय में अतिरिक्त वृद्धि कर सकते हैं। कार्यक्रम में महाविद्यालय के अतिथि डॉ. सत्यनारायण सिंह, अतिथि शिक्षक डॉ. संजय गिलहरे सहित बड़ी संख्या में स्थानीय किसान उपस्थित रहे। इस पहल से किसानों को उन्नत बीज उपलब्ध कराने के साथ ही मसाला फसलों की खेती के प्रति जागरूकता बढ़ाने और कृषि उत्पादन को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।

■ मसाला फसलों की खेती से किसानों को अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए किया जा रहा प्रोत्साहित

सेजेस विद्यालयों को मिले 45 नए शिक्षक और कर्मचारी



■ रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी, जिले की शैक्षणिक व्यवस्था होगी और मजबूत

रायगढ़, 28 नवम्बर। जिले के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों (सेजेस) में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लोक शिक्षण संचालनालय, रायपुर द्वारा चयनित 45 अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इन नियुक्तियों से विद्यालयों में शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की कमी दूर होगी और विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में शैक्षणिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।

कलेक्टर के निर्देशानुसार एवं जिला शिक्षा अधिकारी के मार्गदर्शन और उपस्थिति में नियुक्ति की प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इसके तहत 25 एवं 26 नवंबर को चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इसके पश्चात 27 नवंबर को सभी 45 अभ्यर्थियों की काउंसलिंग आयोजित की गई और उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से जिले के सेजेस विद्यालयों को विभिन्न पदों पर 45 शैक्षणिक एवं अन्य कर्मचारी मिले हैं। इनमें 10 सहायक शिक्षक, 2 प्राथमिक प्रधान पाठक, 3 मिडिल प्रधान पाठक, 5 लैब असिस्टेंट, 10 व्याख्याता, 1 लाइब्रेरियन, 2 व्यायाम शिक्षक तथा 12 शिक्षक शामिल हैं।

जिले में आपात स्थिति के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए

जवानों ने आगजनी, राहत शिविर, घायलों के रेस्क्यू का किया अभ्यास

■ तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

रायगढ़, 28 नवम्बर। जिले में आपात परिस्थितियों के दौरान नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा तथा राहत एवं बचाव कार्यों की तैयारियों को परखने के उद्देश्य से आज नगर सेना कैंप, चांदमारी में नागरिक सुरक्षा (सिविल डिफेंस) के तहत मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इसमें नगर सेना, जिला प्रशासन, पुलिस, एनसीसी, स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारियों ने भाग लिया। अभ्यास के दौरान अलग-अलग आपात परिस्थितियों में त्वरित कार्यवाही, बचाव कार्य और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया। गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार आयोजित इस अभ्यास का उद्देश्य आपदा एवं आपात स्थितियों से निपटने के लिए विभागीय तैयारियों को मजबूत करना और नागरिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाना है।

मॉक ड्रिल में साप्ताहिक बाजार में आपात स्थिति, राहत शिविर तथा सार्वजनिक स्थान पर आग लगने जैसी परिस्थितियों के मॉडल तैयार कर अभ्यास किया गया। इस दौरान आग बुझाने, प्रभावित लोगों को बाहर निकालने, घायलों का रेस्क्यू



करने और उन्हें राहत शिविर तक पहुंचाने की प्रक्रिया का अभ्यास किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी ने बताया कि सिविल डिफेंस के अंतर्गत 12 प्रकार की प्रमुख सेवाओं को शामिल किया गया है। इन सेवाओं के माध्यम से आपातकालीन परिस्थितियों एवं प्राकृतिक आपदाओं के दौरान नागरिकों की जान-माल की सुरक्षा, बचाव और राहत कार्य किए जाते हैं। ऐसी परिस्थितियों में विभिन्न विभागों के बीच बेहतर तालमेल और त्वरित प्रतिक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है। मॉक ड्रिल के माध्यम से यह अभ्यास किया गया कि आपात स्थिति उत्पन्न होने पर किस प्रकार तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रभावित लोगों को सुरक्षित निकाला जाए और समन्वय के साथ राहत एवं बचाव कार्य संचालित किए जाएं।

डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट ब्लासियुस कुजूर ने बताया कि इस तरह के अभ्यास से आपात परिस्थितियों में विभिन्न विभागों की भूमिका और उनकी कार्यप्रणाली को समझने में मदद मिलती है। साथ ही विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर जरूरत के समय त्वरित गति से राहत एवं बचाव कार्य करने की क्षमता मजबूत होती है। इस अवसर पर राजस्व एवं पुलिस विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

एक नजर

शतरंज के सबसे बड़े मंच नेशनल सीनियर ओपन स्पर्धा में खेलेंगी स्नेहा हलधर

डोंगरगढ 28 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। एन.आर.सी.ए.के सयोजक मतीन खान ने बताया की संस्था से जुड़ी पश्चिम बंगाल निवासी सत्रह वर्षीय अंतराष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी कु.



स्नेहा हल्दर पिता भोगीरथ हल्दर को देश की सबसे कठिन शतरंज नेशनल सीनियर ओपन शतरंज स्पर्धा में उनकी रेटिंग के आधार पर सत्तर वी वरीयता प्राप्त हुई है.यह स्पर्धा 29 नवंबर से 10 दिसंबर तक उत्तरप्रदेश में होगी.इस स्पर्धा में देश के सभी राज्यो के शीर्ष वरीयता प्राप्त शतरंज खिलाड़ी भाग ले रहे है. स्नेहा हल्दर पहली बार यह शतरंज स्पर्धा खेल रही है. एन.आर.सी.ए.संस्था के संरक्षक विवेक वासनिक जी ,अध्यक्ष मोहम्मद अज़हर नवाज़,बाबू रॉव,डॉ.मुन्ना लाल नंदेश्वर,वीरेंद्र अग्रवाल,तजिंदर भाटिया,दीपक चौरसिया,शेख इदु, आशीष शर्मा,मतीन खान, सुयशशाह , गौतमरॉव, डी.एल.टेम्भूरकर, मो.शहरयार, रामप्रसाद पाल,ने शुभकामनाएं दी और उज्वल भविष्य की कामना की है।

सुरक्षित बचपन अभियान के तहत ग्राम बिरेझार में रोका गया बाल-विवाह

राजनांदगांव 28 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री विजय कुमार होता के मार्गदर्शन में जिले में बाल विवाह की रोकथाम हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सुरक्षित बचपन अभियान के तहत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम बिरेझर में होने वाले बाल विवाह को रोकने में सफलता प्राप्त हुई। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव श्रीमती प्रीति नागवंशी ने बताया कि ग्राम बिरेझर में बाल विवाह की सूचना मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैरालीगल वॉलंटियर्स (पीएलवी) एवं महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों द्वारा बाल विवाह को रूकवाया गया। उन्होंने बताया कि दस्तावेजों की जांच करने पर वर की आयु 18 वर्ष पाई गई। पीएलवी द्वारा वर वधु के परिजनों, रिश्तेदारो एवं उपस्थित ग्रामवासियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम कानूनी प्रावधान तथा सजा के बारे में जानकारी दी गयी तथा कम उम्र में विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। इस समझाइश के बाद दोनों पक्षों के परिजनों ने लड़के की आयु 21 वर्ष पूर्ण होने पर विवाह की सहमति जताई। बाल विवाह बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यह बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षित भविष्य के अधिकारों का भी उल्लंघन है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 अंतर्गत बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव द्वारा नागरिकों से बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति को रोकने में सक्रिय सहयोग करने की अपील की गई है। कहीं भी बाल विवाह होने की सूचना मिलने पर तत्काल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्थानीय पुलिस अथवा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित कर सकते है।

मोहारा पुन्नी मेला स्थल में फैले कचरे की सफाई में जुटा निगम का अमला

राजनांदगांव 28 नवंबर (तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता)। शहर में सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने निगम का सफाई अमला सफाई में जुटा रहता है। महापौर श्री मधुसूदन यादव एवं निगम आयुक्त श्री जी.आर. मरकाम शहर में साफसफाई का जायजा लेकर सुधार की दिशा में कार्य करने दिशा निर्देश देते है। महापौर एवं आयुक्त के निर्देश पर निगम का स्वास्थ्य अमला मोहारा पुन्नी मेला के पश्चात मेला स्थल में फैले गंदगी की सफाई करने सफाई अभियान चलाया जा रहा है। मेला स्थल में मेले के दौरान बडी मात्रा में कचरा फैल गया था, जिसकी निगम के सफाई कर्मचारियो की टीम द्वारा मौके मे पहुचकर व्यापक स्तर पर साफसफाई की जा रही है। सफाई कर्मचारियो द्वारा मेला स्थल में फैली गंदगी, कचरा,झिल्ली, पन्नी, प्लास्टिक को एकत्रित कर सफाई की जा रही है। नदी के घाट पर फैली गंदगी, की भी सफाई की जा रही है, पूरे क्षेत्र की सफाई होते तक मेला स्थल में अभियान चलाकर सफाई की जावेगी। मेले के सम्पूर्ण क्षेत्र की सफाई कर स्वच्छ वातावरण निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के 62 पंचायत प्रतिनिधियों ने किया सिहावा और सांकरा पंचायत का अध्ययन भ्रमण

आत्मनिर्भर, महिला हितैषी, बाल हितैषी और स्वस्थ पंचायत की अवधारणा समझी, ग्रामसभा एवं पेसा कानून की भी दी गई जानकारी

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

नगरी 28 नवंबर। मध्यप्रदेश पंचायतीराज संस्थाओं के 62 पंचायत प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों का दल 27 नवंबर को धमतरी जिले के नगरी विकासखंड की ग्राम पंचायत सिहावा एवं सांकरा पहुंचा। दल ने दोनों ग्राम पंचायतों का प्रशिक्षण सह अध्ययन भ्रमण कर छत्तीसगढ़ की पंचायत व्यवस्था, ग्रामीण विकास के मॉडल और स्थानीय स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली।

ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण



विकास संस्थान निमोरा, रायपुर के मार्गदर्शन में आयोजित इस अध्ययन भ्रमण का उद्देश्य मध्यप्रदेश के पंचायत प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ की पंचायत व्यवस्था और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में अपनाई जा रही बेहतर व्यवस्थाओं से अवगत कराना था।

आत्मनिर्भर और महिला हितैषी पंचायत की अवधारणा समझी : इस दौरान ग्राम पंचायत सिहावा सचिव मदन सेन द्वारा पंचायत की आय के स्रोत, पंचायत को आत्मनिर्भर बनाने के उपायों तथा आत्मनिर्भर पंचायत, महिला हितैषी पंचायत, बाल हितैषी पंचायत और स्वस्थ पंचायत की अवधारणाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही भारत सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए बताया गया कि इन योजनाओं का लाभ आम जनता तक किस प्रकार पहुंचाया जा सकता है। ग्रामसभा के महत्व, उसके आयोजन और पंचायतों में ग्रामीणों की सहभागिता के साथ ही पेसा कानून के प्रावधानों की भी जानकारी दी गई।

प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानी पंचायत व्यवस्था

प्रशिक्षण के दौरान मध्यप्रदेश से आए पंचायत प्रतिनिधियों ने विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। प्रतिनिधियों ने पंचायत की आय बढ़ाने, सरकारी योजनाओं के लाभ हितग्राहियों तक पहुंचाने, ग्रामसभा की भूमिका और पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने से जुड़े सवाल किए। उपस्थित अधिकारियों ने उनके सवालों का जवाब देते हुए आवश्यक जानकारी प्रदान की। इस संवादात्मक प्रक्रिया से पंचायत प्रतिनिधियों को छत्तीसगढ़ की पंचायत व्यवस्था को नजदीक से समझने का अवसर मिला। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सिहावा की सरपंच उषा देवी नाग, उपसरपंच सुनील सिंहसार सहित ग्राम पंचायत के सदस्य उपस्थित रहे।

विकास सुखवानी रोज ताजी सब्जियां खिलाकर करते हैं गायों की सेवा

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

तिल्दा नेवरा 28 नवंबर। गौमाता को केवल पशु नहीं, बल्कि माता का स्वरूप मानकर उनकी सेवा करना भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसी भावना को जमीन पर उतारते हुए तिल्दा नेवरा में विकास मित्र मंडल के प्रमुख विकास सुखवानी द्वारा एक अनूठी गौसेवा पहल की जा रही है। अक्टूबर माह से शुरू हुआ यह सेवा अभियान लगातार जारी है। इसके तहत प्रतिदिन लगभग 2 हजार से ढाई हजार किलो तक ताजी सब्जियां गौमाता को खिलाने की व्यवस्था की जा रही है।

इस अभियान की सबसे खास और भावुक कर देने वाली तस्वीर तब देखने को मिलती है, जब विकास सुखवानी स्वयं सब्जियां लेकर गौमाता के बीच पहुंचते हैं। वे अपनी एक विशेष सीटी बजाकर गौमाता को आवाज लगाते हैं। सीटी की आवाज सुनते ही आसपास मौजूद गौमाताएं झुंड के झुंड वहां पहुंचने लगती हैं। देखते ही देखते बड़ी संख्या में गौमाताएं एकत्रित हो जाती हैं और सब्जियां खाने लगती हैं। यह दृश्य गौमाता और उनकी सेवा में जुटे व्यक्ति के बीच बने अपनत्व और विश्वास को भी दर्शाता है।

एक साथ बड़ी संख्या में मौजूद गौमाताओं को व्यवस्थित तरीके से सब्जियां खिलाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए धैर्य, समय और लगातार मेहनत की जरूरत होती है। कई बार झुंड



में गौमाताओं को संभालते हुए सभी तक सब्जियां पहुंचाना चुनौतीपूर्ण हो जाता है, लेकिन विकास सुखवानी स्वयं इस जिम्मेदारी को निभाते हुए नजर आते हैं। वे गौमाता को माता का दर्जा देते हुए नियमित रूप से उनके लिए सब्जियों की व्यवस्था करते हैं और अपने हाथों से उन्हें खिलाने पहुंचते हैं।

इस गौसेवा अभियान में प्रतिदिन अलग-अलग प्रकार की ताजी सब्जियां शामिल की जाती हैं। इनमें टमाटर, बैंगन, आलू, पत्ता गोभी, फूल गोभी, धनिया, मूली सहित अन्य मौसमी सब्जियां प्रमुख हैं। हर दिन नई सब्जियों की व्यवस्था कर गौमाता को खिलाया जाता है। प्रतिदिन लगभग 2 से ढाई हजार किलो सब्जियों की व्यवस्था इस अभियान का बड़ा हिस्सा है।

विकास मित्र मंडल का यह गौसेवा अभियान प्रतिदिन रात्रि लगभग 8:30 बजे शुरू होता है। पंडित दीनदयाल चौक से लेकर गोवर्धन नगर और गांधी चौक तक इस सेवा का सिलसिला चलता है। सब्जियां लेकर पहुंचते ही सीटी की आवाज से गौमाताओं को बुलाया जाता है और उन्हें एकत्रित कर सब्जियां खिलाई जाती हैं। तिल्दा नेवरा में अक्टूबर माह से लगातार संचालित यह गौसेवा अभियान अब लोगों के बीच चर्चा का विषय बन रहा है। विकास मित्र मंडल के प्रमुख विकास सुखवानी की यह पहल बताती है कि गौसेवा केवल किसी विशेष पर्व या आयोजन तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसे प्रतिदिन के जीवन का हिस्सा बनाया जा सकता है। गौमाता के प्रति श्रद्धा, समर्पण और सेवा भाव के साथ प्रतिदिन इतनी बड़ी मात्रा में सब्जियों की व्यवस्था करना निश्चित रूप से एक सराहनीय प्रयास है। विकास सुखवानी की इस पहल से समाज के अन्य लोगों को भी गौसेवा और जीवों के प्रति संवेदनशीलता की प्रेरणा मिल रही है। एक सीटी की आवाज, झुंड में पहुंचती गौमाताएं और उनके लिए रोजाना हजारों किलो सब्जियों की व्यवस्था... तिल्दा नेवरा में विकास मित्र मंडल की यह पहल गौसेवा के प्रति समर्पण की एक अलग पहचान बना रही है।

सशिमं माना कैम्प के आचार्य विकास वर्ग में 34 आचार्यों,दीदीयों को दिया प्रशिक्षण

रायपुर 28 नवंबर। शाला में अध्यनरत विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास को सतत् मूल्यांकन के माध्यम से कैसे जांचते हुए अध्ययन के स्तर को बढ़ाते हुए अध्ययन में आगे बढ़ने से पहले पूर्व अध्ययन में रह गई समस्या या कमीयों को कैसे दूर किया जा सके के प्रशिक्षण हेतु शिव शिक्षण समिति, रायपुर द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, माना कैम्प में एक दिवसीय आचार्य विकास वर्ग का आयोजन शाला परिसर में किया गया।

जिसमें शाला में अध्यापन कार्य में कार्यरत 34 आचार्य-दीदीयों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। विकास वर्ग में



विशेष रूप से लक्ष्मण राव मगर, नरेश यादव, बाबुल शाह, प्रमोद मानिक, वीरेंद्र डागा, रामेश्वर साहू उपस्थित रहे।

श्रमिकों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना विभाग की पहली प्राथमिकता

रायपुर, 28 नवंबर। प्रदेश के श्रम, वाणिज्य एवं उद्योग तथा वाणिज्यिक कर मंत्री श्री लखनलाल देवांगन ने आज श्रम विभाग की विभागीय बैठक लेकर जिलावार एवं योजनावार प्रदर्शन की समीक्षा की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि श्रमिकों के कल्याण में प्रदेश सरकार द्वारा अनेक महत्वाकांक्षी व जनहितकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका लाभ दिलाना विभाग की पहली प्राथमिकता है। श्रम मंत्री ने स्पष्ट तौर पर कहा कि अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गम्भीरता दिखाएं और बेहतर प्रदर्शन करें। महानदी मंत्रालय के भूतल स्थित समिति कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में श्रम मंत्री ने आगे कहा कि श्रमिकों के कल्याण व उनके हितों की रक्षा किस तरह से हो।

नागसेन बौद्ध विहार में मनाया गया भारतीय संविधान दिवस, बाबा साहेब को किया नमन



तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

डोंगरगढ़ 28 नवंबर। भारतीय संविधान दिवस के अवसर पर आदर्श बौद्ध महासभा नागसेन बौद्ध विहार में कार्यक्रम आयोजित कर संविधान दिवस श्रद्धा एवं सम्मान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर सर्वप्रथम बुद्ध वंदना की गई। इसके पश्चात भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए भारतीय संविधान के महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही संविधान में निहित समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं न्याय के आदर्शों को आत्मसात करने का संकल्प लिया। तहसील परिसर में स्थित भारत रत्न डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुवे बौद्ध अनुयायियों के द्वारा जयघोष के नारे लगाए गए। इस अवसर पर संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया,कार्यक्रम में बौद्ध भिक्षु सहित बौद्ध समाज के उपासक उपासिकाएं लोगों की उपस्थिति रही। संविधान दिवस के अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों ने भी तहसील परिसर में स्थित आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन करते हुवे जयघोष के नारे लगाते हुवे संविधान के प्रस्तावना का वाचन किया गया।

पुलिस अधीक्षक सुश्री अंकिता शर्मा ने किया पुलिस थाना घुमका का वार्षिक निरीक्षण



तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजनांदगांव, 28 नवंबर। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव सुश्री अंकिता शर्मा द्वारा आज पुलिस थाना घुमका का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण का उद्देश्य थाना की कार्यप्रणाली, पुलिसिंग व्यवस्था, अभिलेखों के संधारण एवं कानून-व्यवस्था से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए पुलिस कार्यों को और अधिक प्रभावी एवं जनोन्मुखी बनाना रहा।

निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सर्वप्रथम थाना में उपस्थित अधिकारी-कर्मचारियों का टर्नआउट चेक किया गया तथा थाना क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति, अपराधों की प्रकृति, कानून-व्यवस्था एवं पुलिसिंग से संबंधित आवश्यक जानकारी प्राप्त की गई।

पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना के दैनिक कार्यों, अपराधों की विवेचना एवं लंबित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान अपराधों के निराकरण, लंबित शिकायतों, विवेचनाधीन मामलों एवं माननीय न्यायालय से संबंधित कार्यों की स्थिति का जायजा लिया गया।

थाना के रोज़नामचा, विभिन्न रजिस्टरों एवं अभिलेखों के संधारण, ष्टष्ट्रञ्जह्र कार्यप्रणाली, ऑनलाइन अभिलेखों के अद्यतन एवं वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त निर्देशों के पालन की भी जांच की गई। लंबित मामलों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने तथा विवेचना की गुणवत्ता बनाए रखने हेतु संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान थाना के रिकॉर्ड रूम, मालखाना, वायरलेस व्यवस्था, संचार प्रणाली एवं बलवा ड्रिल सामग्री का अवलोकन किया गया। उपलब्ध संसाधनों के उचित रखरखाव, अभिलेखों के नियमानुसार संधारण तथा पुलिस कार्यों में तकनीकी संसाधनों के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। पुलिस अधीक्षक ने थाना क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने, अपराध नियंत्रण एवं आम नागरिकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

सड़क की लड़ाई में भाजपा नेता भी भ्रष्ट और ठेकेदार लोग भी: मदन साहू

विभागीय अधिकारी भी दूध के धुले नहीं जांच कार्यवाही जरूरी

तरुण छत्तीसगढ़ संवाददाता

राजनांदगांव 28 नवंबर। कवर्धा से राजनांदगांव होते हुए मानपुर तक प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य को लेकर भाजपा नेता और निर्माण कंपनी के बीच चल रहा विवाद अब राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर भाजपा नेता एवं शैडो विधायक भारत वर्मा तथा संबंधित ठेकेदार के बीच आरोप-प्रत्यारोप का मामला लगातार सुर्खियों में है। अब इस विवाद में जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष मदन साहू ने हस्तक्षेप करते हुए भाजपा नेता, ठेकेदार और विभागीय अधिकारियों की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े



किए हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

श्री साहू ने कहा कि सड़क निर्माण जैसे महत्वपूर्ण जनहित के कार्य में यदि गुणवत्ता और भ्रष्टाचार को लेकर विवाद सामने आ रहा है तो इसकी जिम्मेदारी केवल ठेकेदार तक सीमित नहीं होनी चाहिए। निर्माण कार्य की निगरानी करने वाले विभागीय अधिकारियों की भूमिका की भी बारीकी से जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क की लड़ाई में भाजपा नेता भी सवालों के घेरे में हैं और ठेकेदार पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं विभागीय अधिकारी भी दूध के धुले नहीं हैं। ऐसे में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है। श्री साहू ने कहा कि सड़क निर्माण में शासन की बड़ी राशि खर्च होती है और इसका सीधा लाभ आम जनता, किसानों, व्यापारियों तथा क्षेत्र के नागरिकों को मिलना चाहिए। यदि निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता हुआ है या किसी स्तर पर अनियमितता और भ्रष्टाचार को संरक्षण दिया गया है तो यह जनता के साथ धोखा है। उन्होंने कहा कि केवल आरोप-प्रत्यारोप लगाकर मामले को दबाया नहीं जाना चाहिए, बल्कि निर्माण कार्य से संबंधित स्वीकृति, तकनीकी मापदंड, गुणवत्ता परीक्षण, भुगतान प्रक्रिया और विभागीय निगरानी की पूरी पड़ताल होनी चाहिए। उन्होंने कलेक्टर से मांग की कि पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों, निर्माण एजेंसी और ठेकेदार की भूमिका की अलग-अलग जांच कराई जाए। यह भी पता लगाया जाए कि सड़क निर्माण में निर्धारित मापदंडों का पालन हुआ है या नहीं और जिम्मेदार अधिकारियों ने अपने दायित्वों का निर्वहन ईमानदारी से किया है या नहीं। जांच में अनियमितता अथवा भ्रष्टाचार प्रमाणित होने पर संबंधित लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। श्री साहू ने कहा कि इस विवाद को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी अपना बयान दे चुके हैं। ऐसे में यह मामला अब केवल एक नेता और ठेकेदार के बीच का विवाद नहीं रह गया है बल्कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता, सरकारी धन के उपयोग और प्रशासनिक जवाबदेही से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है। उन्होंने कहा कि जनता को इस पूरे मामले की सच्चाई जानने का अधिकार है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य में राशनकार्डधारियों को मिल रहा नियमित खाद्यान्न

रायपुर, 28 नवंबर। प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत संचालित राज्य की 14,193 उचित मूल्य दुकानों के जरिए 83.27 लाख राशन कार्डधारियों को निर्धारित पात्रतानुसार चावल, नमक, शक्कर, चना और केरोसिन का नियमित आबंटन व वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। केरोसिन लगभग 74 लाख अंत्योदय व प्राथमिकता राशनकार्डधारियों के लिए है। केरोसिन 62 रुपये से 82 रुपये प्रति लीटर निर्धारित होने के कारण हितग्राहियों द्वारा उठाव कम खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने जारी बयान में कहा है कि जनवरी 2026 से नवंबर 2026 तक प्रदेश में 26.51 लाख टन चावल, 95,832 टन नमक, 62,083 टन शक्कर और 36,244 टन चना का बड़े पैमाने पर राशनकार्डधारियों को पात्रतानुसार वितरण किया गया है। केवल नागरिक आपूर्ति निगम के प्रदाय केन्द्रों में उपलब्धता न होने के कारण जुलाई 2026 से चना तथा अक्टूबर 2026 से शक्कर का वितरण अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ है।

छत्तीसगढ़ शासन

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड, राजनांदगांव (छ.ग.)

छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25 गौरव उत्सव स्वर्णिम संकल्प

✆ 07744-299703 ✉ eeraj-phe-cg@nic.in

// निविदा आमंत्रण सूचना//

(रिस्क एंड कास्ट)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से प्रपत्र- 'ए' में जल जीवन मिशन अंतर्गत जल जीवन मिशन अंतर्गत एकल ग्राम/रेट्रोफिटिंग योजनांतर्गत राजनांदगांव के विभिन्न विकासखंडों के विभिन्न ग्रामों में रिस्क एवं कास्ट में शेष बचे कार्य जिसमें UPVC/HDPE पाईप लाईन जोड़ने बिछाने, उच्चस्तरीय जलागार निर्माण, स्वीच रूम, उच्चस्तरीय जलागार के चारो ओर बाउंड्रीवॉल निर्माण, सबमर्सिबल पंप का प्रदाय एवं स्थापना कार्य, विद्युत विभाग (CSPDCL) से इलेक्ट्रिक कनेक्शन, इलेक्ट्रोक्लोरीनेटर स्थापना, क्लोरीनेटर रूम, घरों एवं शासकीय संस्थानों में कार्यरत नल कनेक्शन प्रदाय आदि एवं अन्य समस्त कार्य, टेस्टिंग, 03 माह का ट्रायल रन, 06 माह तक संचालन संधारण का कार्य (सम्पूर्ण कार्य सामग्री सहित, संलग्न शेड्युल अनुसार) की निविदाएं दिनांक 25.11.2026 से ऑन लाईन पर आमंत्रित की जाती है।

उपरोक्त कार्य के निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in से दिनांक 02.12.2026 से डाउनलोड की जा सकती है तथा निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक 16.12.2026 (शाम 5:30 बजे) तक है।

निविदा में जारी एस.ओ.आर. PHE दिनांक 01.06.2020 से लागू एवं संशोधन 05/2021.22 तक तथा PWD 2015 का दिनांक 07.04.2016 से लागू समस्त संशोधन सहित पर तैयार किया गया है।

क्र.	निविदा क्रमांक	सिस्टम क्रमांक	विकासखण्ड	योजना/ ग्राम का नाम	निविदा की लागत (रू. लाख में)	आमंत्रण का प्रकार
1	16	204531	डोंगरगांव	सोनेसरार	12.71	सप्तम
2	17	204532	डोंगरगढ़	मांगीखुंटा, दमउदहरा, गुडरी	65.23	तृतीय
3	18	204533	डोंगरगांव	सिवनीखुर्द, घुघवा	89.73	द्वितीय

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड
राजनांदगांव (छ.ग.)

जी-262704749/8

एक नजर

कोचिंग कन्वर्सेशन्स के लिए शैलेश अग्रवाल का चयन

रायपुर 28 नवंबर। लायंस इंटरनेशनल द्वारा हिंदुस्तान के चुनिंदा लॉयंस के लिए आई आई एम



कोझीकोड में आयोजित किए जा रहे प्रतिष्ठित नेतृत्व विकास कार्यक्रम कोचिंग कन्वर्सेशन्स के लिए छत्तीसगढ़ के पीएमजेएफलायन शैलेश अग्रवाल का चयन किया गया है। यह चयन उनके उत्कृष्ट नेतृत्व, लायंस संगठन में योगदान तथा नेतृत्व विकास के क्षेत्र में उनकी सक्रिय भूमिका का सम्मान है। यह विशेष कार्यक्रम 23 एवं 24 नवंबर को भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोझिकोड (केरल) में आयोजित किया जाएगा। दो दिवसीय इस विशेष प्रशिक्षण एवं नेतृत्व विकास कार्यक्रम की मेजबानी आईआईएम कोझिकोड द्वारा की जाएगी।

केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय एवं विप्र कॉलेज के बीच एमओयू

रायपुर 28 नवंबर। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने विप्र कॉलेज के साथ संस्कृत अध्ययन केंद्र संचालित करने के लिए एम.ओ.यू .किया। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के निदेशक प्रो. रतनमोहन झा के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर करते हुए विप्र कॉलेज के प्राचार्य डॉ.मेघेश तिवारी ने बताया कि संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय (पूर्व में राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान मानित विश्वविद्यालय शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन) के साथ एमओयू करने का उद्देश्य विद्यार्थियों में संस्कृत भाषा सीखने को लिए प्रेरित करना है। विप्र कॉलेज के प्राचार्य डॉ मेघेश तिवारी ने जानकारी देते हुए कहा छत्तीसगढ़ में पहला महाविद्यालय है जिसने प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होने के पश्चात विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट कोर्स करने से न केवल संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त होगा बल्कि क्रेडिट स्कोर भी अर्न करेंगे। प्राचार्य डॉ मेघेश तिवारी ने केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से एमओयू के लिए रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ सच्चिदानंद शुक्ला के प्रति आभार व्यक्त किया, जिनकी प्रेरणा व प्रयासों से सम्भव हुआ।उन्होंने कहा।

कांग्रेस में जूतम-पैजार और गुटबाजी चरम पर : भाजपा

रायपुर 28 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुनील चौधरी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस की आंतरिक कलह, गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की दयनीय स्थिति पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस में आज कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हैसियत क्या रह गई है, यह खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं के बयान ही उजागर कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो अपने ही कार्यकर्ताओं को 'स्लीपर सेल' तक बता चुके हैं, जो कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता चौधरी ने शुक्रवार को यहाँ एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज को हटाने और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कमजोर करने की चल रही कवायद पर कटाक्ष किया और छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी सुखदेव भगत के हालिया दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस प्रभारी ने निष्क्रिय कार्यकर्ताओं को हटाने की बात कही है। चौधरी ने सवाल उठाया कि क्या यह सीधा संकेत कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैज के लिए है, जो इन दिनों केवल प्रवक्ता की भूमिका तक सीमित हैं और मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं? दूसरी ओर भिलाई विधायक देवेन्द्र यादव ने पूरे प्रदेश में पदयात्रा की घोषणा कर दी है। बैज को हटाने और यादव को मजबूत करने की इस पूरी कवायद को उन्हें (बघेल को) राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिश मान रहे भूपेश बघेल को भय सता रहा है।

4-5 दिसम्बर को होगा राज्य स्तरीय युवा महोत्सव

रायपुर 28 नवंबर। प्रदेश के युवाओं की कला, संस्कृति और रचनात्मक प्रतिभाओं का संगम आगामी 4 दिसम्बर और 5 दिसम्बर को बिलासपुर के बहतराई स्थित स्वर्गीय बी.आर. यादव राज्य खेल प्रशिक्षण केंद्र में होगा। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में प्रदेश के सभी 33 जिलों से लगभग तीन हजार प्रतिभागी शामिल होंगे। महोत्सव के उद्घाटन एवं समापन समारोह आउटडोर स्टेडियम में प्रस्तावित हैं, जिनमें मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे। खेल एवं युवा कल्याण विभाग की संचालक श्रीमती आकांक्षा शिक्षा खलखो ने आज आयोजन स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने मुख्य मंच, अतिथियों एवं कलाकारों के ग्रीन रूम सहित विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी तैयारियां 30 नवम्बर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव में लोकनृत्य, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला, निबंध लेखन और पारंपरिक वेशभूषा सहित विभिन्न विधाओं में युवा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। आउटडोर स्टेडियम के मुख्य मंच पर उद्घाटन एवं समापन समारोह के साथ सांस्कृतिक संध्या और लोकनृत्य का आयोजन होगा। इंडोर स्टेडियम में लोकगीत एवं चित्रकला, कबड्डी हॉल में नुक्कड़ नाटक तथा अतिरिक्त डोम में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग एवं पीपीटी प्रस्तुतियां होंगी।

धान खरीदी के लिए उपसंग्रहण केंद्र बनाने मुख्य सचिव के निर्देश

रायपुर 28 नवंबर। मुख्य सचिव विकासशील ने आज यहां मंत्रालय में राजस्व प्रशासन, प्रदेश में की जा रही धान खरीदी, सुशासन एवं अभिशरण विभाग में संबंधित कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने नागरिकों की सुविधा के लिए राजस्व विभाग में रिफार्म के संबंध में अधिकारियों से विस्तार से विचार-विमर्श कर जानकारी ली। बैठक में मुख्य सचिव ने प्रदेश में की जा रही धान खरीदी की समीक्षा करते हुए सहकारी समितियों में धान संग्रहण के साथ बनाये उपार्जन केन्द्रों में संग्रहण और आवश्यकतानुसार उप संग्रहण केन्द्र बनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए है।

मुख्य सचिव ने धान बेचने वाले किसानों को समय पर भुगतान, बारदानों की पर्याप्त व्यवस्था, उपार्जन केन्द्रों में धान का सुरक्षित भंडारण के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्य सचिव विकासशील ने समितियों में धान के भौतिक सत्यापन कर धान के उठाव के संबंध में अधिकारियों को निर्देशानुसार कार्यवाही करने के लिए कहा। मुख्य सचिव ने कलेक्टरों को धान खरीदी व्यवस्था की लगातार मानिटरिंग करने के निर्देश दिए हैं।

श्री विकासशील ने सीएम हेल्प लाइन से शिकायतों के आसान एवं तेजी से निराकरण के लिए की जा रही नई व्यवस्थाओं के संबंध में अधिकारियों से चर्चा की। बैठक में मुख्यमंत्री एवं सुशासन एवं अभिशरण विभाग के सचिव राहुल भगत ने कहा कि अब शिकायतकर्ता नागरिकों की संबंधित अधिकारी से सीधा संवाद



करने की व्यवस्था की विस्तार से जानकारी दी।

बैठक में गृह एवं जेल विभाग के अपर मुख्य सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव सुश्री रीना बाबा साहेब कंगाले, राजस्व विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं संभागायुक्त तथा जिलों के कलेक्टर शामिल हुए।

आत्मानंद स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन के लिए 71.57 करोड़ मंजूर

रायपुर 28 नवंबर। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के 12 जिलों में संचालित स्वामी आत्मानंद स्कूलों के कर्मचारियों के वेतन के लिए कुल 71 करोड़ 57 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस संबंध में विभाग की ओर से आदेश जारी किया गया है।

जारी आदेश के अनुसार, अलग-अलग जिलों को उनकी आवश्यकता के आधार पर राशि आवंटित की गई है। इस सूची में बिलासपुर को सबसे अधिक 29.06 करोड़ रुपये मिले हैं, जबकि दंतेवाड़ा को सबसे कम 1.39 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

डीपीआई की ओर से जारी स्वीकृति में बिलासपुर जिले को 2,906 लाख रुपये यानी 29 करोड़ 6 लाख रुपये दिए गए हैं। इसके बाद सूरजपुर को 747 लाख रुपये (7 करोड़ 47 लाख) और सक्ती जिले को 610.50 लाख रुपये (6 करोड़ 10 लाख 50 हजार) की मंजूरी मिली है। वहीं मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी



जिले के लिए 531 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं। 12 जिलों के लिए 71.57 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति से स्वामी आत्मानंद स्कूलों में पदस्थ शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। लंबे समय से वेतन व्यवस्था को लेकर इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए इसे राहत भरा कदम माना जा रहा है। हालांकि, राशि स्वीकृत होने के बाद संबंधित जिलों में वास्तविक भुगतान कब तक होगा, यह आगे की विभागीय और जिला स्तर की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।

परिसीमन भाजपा का खतरनाक खेल : शैलेश

रायपुर, 28 नवम्बर। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि देश के लोकतंत्र के सामने आज एक बहुत बड़ा खतरा खड़ा है। भाजपा सरकार महिला आरक्षण का नाम लेकर एक और बड़ा राजनीतिक खेल खेल रही है। यह महिला सशक्तिकरण का बिल नहीं है, यह परिसीमन का बिल है। यह संविधान पर हमला है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि यह संघीय ढांचे को कमजोर करने और दक्षिण भारत, पंजाब और छोटे राज्यों की आवाज को कुचलने का प्रयास है। सितंबर 2023 में संसद ने सर्वसम्मति से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया था। कांग्रेस ने उसका समर्थन किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तुरंत लागू करने की मांग की थी। लेकिन मोदी-शाह सरकार ने उसे लगभग तीन साल तक ठंडे बस्ते में डाल



रखा। अधिसूचना भी अप्रैल 2026 में रात के अंधेरे में जारी की गई। अब वही सरकार कह रही है कि ÷महिला आरक्षण के लिए÷ विशेष सत्र बुलाया गया है। यह साफ झूठ है।

कांग्रेस की मांग साफ और न्यायसंगत है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा है कि जनसंख्या नियंत्रण में सफल रहे दक्षिणी राज्य, पंजाब और छोटे राज्य अगर जनसंख्या नियंत्रण के आधार पर सीटें खोते हैं, तो यह उनके अच्छे काम की सजा है। क्या परिवार नियोजन करने वाले राज्यों को सजा दी जाएगी? क्या उत्तर की जनसंख्या वृद्धि को राजनीतिक इनाम दिया जाएगा? यह संघीय ढांचे के खिलाफहै। यह देश की एकता के खिलाफहै। राहुल गांधी ने साफकहा है, यह महिला बिल नहीं, भारत के चुनावी नक्शे को बदलने का प्रयास है।

सरकार की बदनीयती से किसान परेशान : सुशील

रायपुर 28 नवंबर। धान खरीदी की सुस्त चाल, खसरा-रकबा उलझन और केंद्रों की अव्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है कि इस सरकार की बदनीयती से प्रदेश के किसान परेशान हैं। 160 लाख टन लक्ष्य के मुकाबले शुरुआती 11 दिनों में 5 प्रतिशत खरीदी भी नहीं हो पायी है, जबकि छुट्टी के दिनों को छोड़ कर इस खरीफ सीजन में कुल 47 दिन ही खरीदी होना है ऐसे में शेष 36 दिनों में 95 प्रतिशत लक्ष्य असंभव है।

यह सरकार किसानों का पूरा धान खरीदना नहीं चाहती इसलिए खरीदी धीमी गति से की जा रही है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा है किएक तरफ यह



सरकार दावा करती है कि जिन किसानों ने पिछले साल धान खरीदी के लिए अग्रि स्टैक पोर्टल पर पंजीयन कराया है उन्हें दोबारा पंजीयन करवाने की जरूरत नहीं है लेकिन प्रदेश के हजारों किसान ऐसे हैं जिन्होंने जिस खसरे और रकबा का पंजीय करवाया है, पिछले साल उसी पंजीयन के आधार पर जारी टोकन से धान बेचा है उनका रकबा इस साल पोर्टल पर शून्य दिखा रहा है। लाखों किसानों के करबा कम प्रदर्शन हो रहे हैं, कई किसानों के धान के फसल को पोर्टल पर अन्य फसल दिखाया जा रहा है, आखिर यह गड़बड़ी कर कौन रहा है? खसरा-फसल विसंगतियों, भौतिक सत्यापन की नई कवायद और खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं को लेकर किसानों में असमंजस और परेशानी बनी हुई है।

मोदी के सेवा संकल्प को जन जन तक पहुंचाने के लिए भाजपा का सेवा दूत अभियान

रायपुर 28 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी द्वारा संचालित 'सेवा दूत अभियान' के अंतर्गत भाजपा किसान नेता एवं सर्व हिंदू सनातन संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश तिवारी को पंडरिया विधानसभा क्षेत्र का सेवा दूत बनाया गया है। इस महत्वपूर्ण दायित्व के तहत योगेश तिवारी 1 दिसंबर से 25 दिसंबर 2026 तक पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में के हर मंडल में पांच दिन का प्रवास करेंगे ।और निर्धारित अवधि में जनसंपर्क, सेवा गतिविधियों तथा संगठनात्मक कार्यों में सहभागिता निभाएंगे। भाजपा का सेवा दूत अभियान पुरे देश मे एक साथ हर विधानसभा म प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में सेवा एवं समर्पण के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान 1 दिसंबर से प्रारंभ होकर 25 दिसंबर तक चलेगा। अभियान का समापन 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर होगा, जो पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी है। छत्तीसगढ़ के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों तक पहुंचेगा अभियान छत्तीसगढ़ में भाजपा द्वारा सेवा दूत अभियान को प्रदेशव्यापी स्तर पर संचालित किया जा रहा है।



विशेष सत्र की आड़ में संविधान पर हमला : बैज

रायपुर 28 नवंबर। 30 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच बुलाये गये संसद के विशेष सत्र को लोकतांत्रिक और संसदीय परंपराओं का भद्दा मजाक बताते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि सरकार नियमित शीतकालीन सत्र से क्यों भाग रही है। मोदी सरकार जल्दबाजी में विशेष सत्र बुलाकर ऑपरेशन लोटस व दलबदल के जरिए जुटाए गए बहुमत से संविधान संशोधन का खेल खेलना चाहती है। विपक्ष को विश्वास में लिए बिना दलबदल के दागदार बहुमत के दम पर संविधान से छेड़छाड़ करना चाहती है। कांग्रेस 2029 से महिला आरक्षण लागू करने के पक्ष में है, वर्तमान सीटों पर ही बिना किंतु परंतु के महिला आरक्षण तत्काल लागू करवाएं सरकार लेकिन जनगणना के आंकड़े आए बिना और जातिगत जनगणना को आधार बनाए बिना परिसीमन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा सरकार लगातार संसदीय मर्यादाओं को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। 2011 के



बाद से दशकीय जनगणना लंबित रहने और दूसरे चरण के आंकड़े सामने आए बिना परिसीमन की जल्दबाजी नीतिगत रूप से अपरिपक्व और संदेह के घेरे में है। जातिगत जनगणना को परिसीमन का आधार न बनाने की मंशा स्पष्ट रूप से ओबीसी वर्ग के अधिकारों और उचित हिस्सेदारी से बचने की रणनीति दिखाती है। क्या सरकार मानती है कि जातिगत जनगणना को परिसीमन का आधार न बनाकर वह जानबूझकर ओबीसी वर्ग को उसके अधिकार और हिस्सेदारी से वंचित रखना चाहती है?

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि परिसीमन और जनगणना के आंकड़ों से जुड़ा कोई भी जल्दबाजी भरा फैसला सीधे प्रतिनिधित्व और हिस्सेदारी को प्रभावित करता है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट है कि इसे 2029 के चुनावों से लागू किया जाना चाहिए, जबकि भाजपा ऑपरेशन लोटस और दलबदल से बने कथित दो-तिहाई बहुमत की आड़ में संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रही है।

16वें राष्ट्रीय एक्सपो का शुभारंभ



रायपुर, 28 नवम्बर। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक राजधानी रायपुर स्थित साइंस कॉलेज ग्राउंड में आज 16वें राष्ट्रीय एक्सपो (स्टील एवं पावर) का विधिवत एवं भव्य शुभारंभ हो गया। यह चार दिवसीय औद्योगिक प्रदर्शनी 27 से 30 नवम्बर 2026 तक आयोजित की जा रही है, जो प्रदेश एवं मध्य भारत के उद्योग जगत को आधुनिक तकनीकों, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और नवाचारों से जोड़ने का एक सशक्त एवं प्रभावशाली मंच प्रदान कर रही है। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में लोकेश परगनिया (संयुक्त निदेशक, एमएसएमई डीएफओ, रायपुर) तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में अश्विनी गर्ग (अध्यक्ष, उरला इंडस्ट्रीज़ एसोसिएशन, रायपुर) सहित एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर आयोजक संस्था इंदौर इन्फोलाइन प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजकुमार अग्रवाल तथा देश-प्रदेश से आए विभिन्न प्रदर्शकों की गरिमामयी उपस्थिति में एक्सपो को औपचारिक रूप से विज़िटर्स के लिए खोल दिया गया। एक्सपो के पहले ही दिन रायपुर के साथ-साथ भिलाई और बिलासपुर सहित आसपास के अन्य शहरों से बड़ी संख्या में व्यापारिक एवं तकनीकी विज़िटर्स साइंस कॉलेज ग्राउंड पहुँचे। उद्घाटन के पहले ही दिन प्रदर्शकों को अपने उत्पादों, मशीनरी और सेवाओं को लेकर बेहद सकारात्मक और उत्साहजनक प्रतिसाद मिला, जिससे पूरे परिसर में औद्योगिक उत्साह और व्यावसायिक संवाद का वातावरण देखने को मिला।

विकसित हो रहे स्टेशनों व निर्माणाधीन कार्यों का दयानंद ने लिया जायजा

रायपुर 28 नवंबर। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, रायपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक दयानंद ने आज दुर्ग-दल्लीराजहरा रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित बालोद एवं भानुप्रतापपुर स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं का गहन अवलोकन किया। उन्होंने रेल संरक्षा, यात्री सुविधाओं के विकास, स्टेशन परिसर में उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं तथा परिचालन संबंधी व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस अवसर पर रायपुर रेल मंडल के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित



पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।

निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने रेलखंड में निर्माणाधीन रोड अंडर ब्रिज (आरयूबी) के कार्यों का जायजा लिया। इसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए जा रहे मरौदा एवं दल्लीराजहरा स्टेशनों की स्टेशन बिल्डिंग एवं अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने योजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता एवं निर्धारित कार्ययोजना के अनुरूप क्रियान्वयन की समीक्षा की।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दयानंद ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। साथ ही निर्माण कार्यों के दौरान यात्रियों की सुविधा, सुरक्षा एवं रेल संरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि निर्माण गतिविधियों के कारण यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो तथा रेल परिचालन सुचारु रूप से संचालित होता रहे।



कौशल किशोर मिश्र प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी की ओर से तरुण छत्तीसगढ़, तरुण छत्तीसगढ़ प्रेस टॉवर, प्रेस काम्पलेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) से मुद्रित एवं प्रकाशित प्रधान संपादक- कौशल किशोर मिश्र, पंजी. क्रं. 45088/85 डाक पं.छ.ग./रायपुर संभाग/33/2024-26